वर्ष: 5 अंक: 18

16-31 मार्च, 2025 (नि:शुल्क)

न्यू इंडिया समाचार

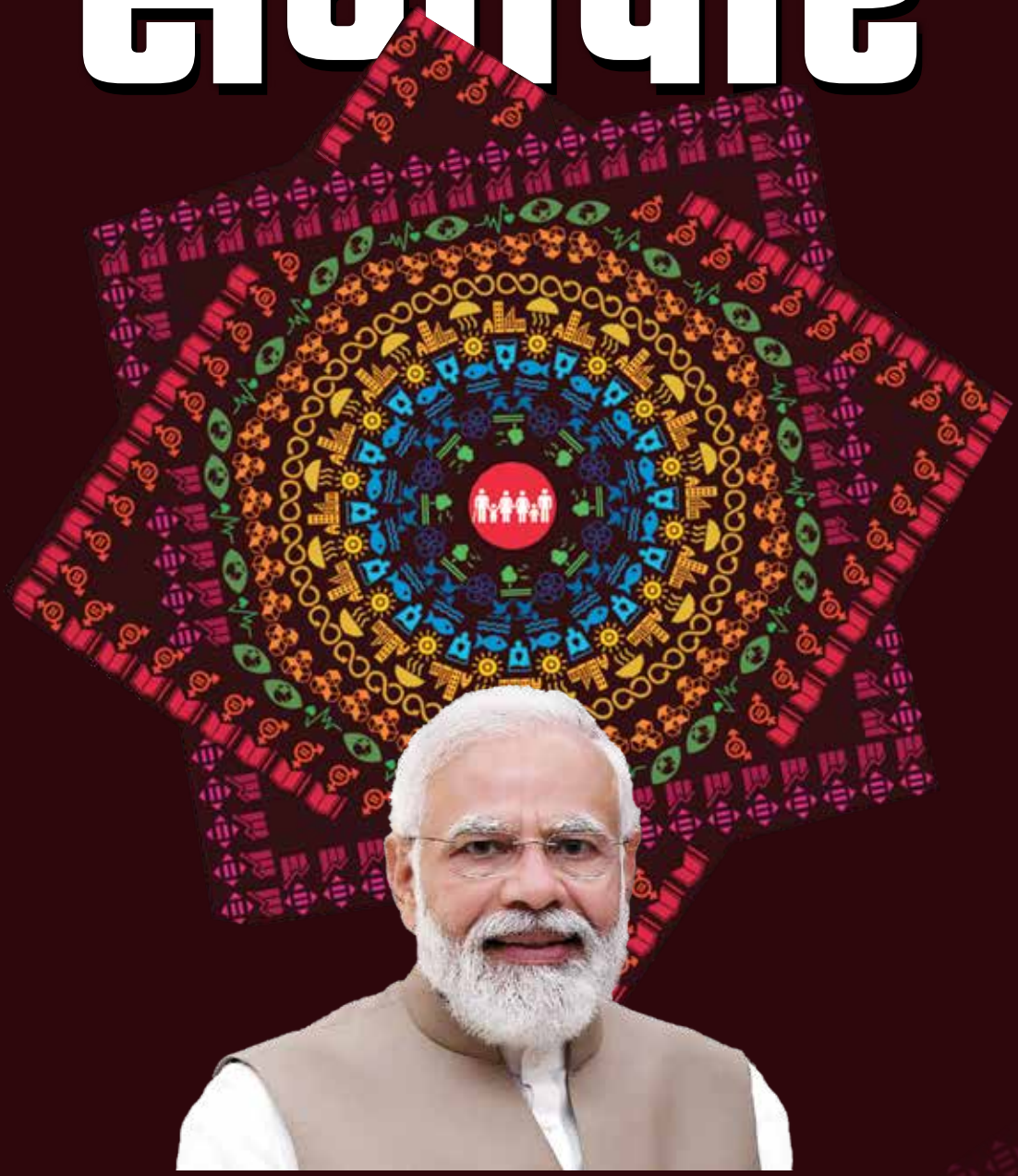

विकसित भारत का मार्ग

संतुष्टिकरण

समान विकास के बिना सतत विकास अधूरा है, इसलिए बीते एक दशक में भारत ने 'सबका साथ, सबका विकास' मंत्र से सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) की दिशा में बढ़ाए हैं निर्णायक कदम...

भारत में तेजी से फैलते मोटापे को हमें रोकना चाहिए : प्रधानमंत्री

मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपील करते हैं वह अक्सर जनांदोलन बन जाता है। मन की बात की 119वीं कड़ी में पीएम मोदी ने मोटापे से मुक्ति की पहल की एवं इसके लिए 10% तेल का कम उपयोग करने का आह्वान किया ताकि एक फिट और स्वस्थ राष्ट्र बनने के दिशा में मोटापे की समस्या से निपटा जा सके। साथ ही, पीएम मोदी ने हर क्षेत्र में महिलाओं के उल्लेखनीय योगदान सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। प्रस्तुत है मन की बात के अंश...

- **चुनौती दें :** मैं 10 लोगों से आग्रह करूंगा। चैलेंज करूंगा कि क्या वो अपने खाने में तेल को 10% कम कर सकते हैं? और साथ ही उनसे यह आग्रह भी करूंगा कि वो आगे नए 10 लोगों को ऐसी ही चुनौती दें।

- **छोटे-छोटे बदलाव :** खाने में तेल का कम उपयोग और मोटापे से निपटना यह केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं है, बल्कि परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। खानपान में तेल का अधिक इस्तेमाल हृदय रोग, मधुमेह और हाइपर टेंशन जैसी ढेर सारी बीमारियों की वजह बन सकता है। अपने खानपान में बदलाव लाकर हम अपने भविष्य को मजबूत, फिट और रोगमुक्त बना सकते हैं।

- **नई क्रांति :** स्पेस सेक्टर हो या फिर एआई युवाओं की बढ़ती भागीदारी एक नई क्रांति को जन्म दे रही है। नई-नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और आजमाने में भारत के लोग किसी से पीछे नहीं हैं। बीते 10 वर्ष में ही करीब 460 सेटेलाइट लांच किए गए। इसमें दूसरे देशों के भी बहुत सारे सेटेलाइट शामिल हैं। हाल के वर्षों की एक बड़ी बात यह भी रही है कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक की हमारी टीम में नारी-शक्ति की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।

- **वैश्विक खेल महाशक्ति :** उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों में देशभर के 11,000 से अधिक एथलीट ने शानदार प्रदर्शन किया। इस खेल ने यह दिखाया कि कभी हार न मानने वाले 'जीतते' जरूर हैं। कंफर्ट के साथ कोई चैंपियन नहीं बनता। मुझे खुशी है कि युवा एथलीटों के दृढ़ संकल्प और अनुशासन के साथ भारत आज वैश्विक खेल महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस :** भारत तेजी से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। हाल ही में, मैं एआई के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गया था। वहां दुनिया ने इस सेक्टर में भारत की प्रगति की खूब सराहना की। देश के लोग एआई का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं, इसके उदाहरण भी हमें देखने को मिल रहे हैं।

- **जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र :** हमारे यहां वनस्पति और जीव-जंतुओं का एक बहुत ही जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र है। ये वन्यजीव हमारे इतिहास और संस्कृति में रचे-बसे हुए हैं। कई जीव-जंतु देवी-देवताओं की सवारी के तौर पर भी देखे जाते हैं।

- **पूजन की परंपरा :** मध्य भारत में कई जनजातियां बाघेश्वर की पूजा करती हैं। महाराष्ट्र में वाघोबा के पूजन की परंपरा रही है। भगवान अयप्पा का भी बाघ से बहुत गहरा नाता है। सुंदरवन में बोनबीबी की पूजा-अर्चना होती है, जिनकी सवारी बाघ है।

- **वन्यजीव संरक्षण :** मैं अपने आदिवासी भाई-बहनों का बहुत आभार करूंगा, क्योंकि वो वन्यजीव संरक्षण से जुड़े कार्यों में बढ़-चढ़कर भागीदारी करते हैं। कर्नाटक के बीआरटी बाघ अभयारण्य में बाघों की आबादी में लगातार वृद्धि हुई है। इसका बहुत श्रेय सोलिगा जनजाति को जाता है, जो बाघ की पूजा करते हैं।

क्यों महत्वपूर्ण है पीएम मोदी का अह्वान

जीवन जीने की औसत आयु में एक साल की बढ़ोतरी देश की जीडीपी में 4% की वृद्धि कर सकती है।

'मन की बात' पूरी सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें।

न्यू इंडिया
समाचार

वर्षः 5, अंकः 18 । 16-31 मार्च, 2025

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र ओझा
प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

मुख्य सलाहकार संपादक
संतोष कुमार

सलाहकार संपादक
विभोर शर्मा

वरिष्ठ सहायक सलाहकार संपादक
पवन कुमार

सहायक सलाहकार संपादक
अखिलेश कुमार
चन्दन कुमार चौधरी

भाषा संपादन
सुमित कुमार (अंग्रेजी)
रजनीश मिश्रा (अंग्रेजी)
नदीम अहमद (उर्दू)

चीफ डिजाइनर
श्याम तिवारी

सीनियर डिजाइनर
फूलचंद तिवारी

डिजाइनर
अभय गुप्ता
सत्यम सिंह

13 भाषाओं में उपलब्ध न्यू इंडिया समाचार को पढ़ने के लिए क्लिक करें।

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

न्यू इंडिया समाचार के पुराने अंक पढ़ने के लिए क्लिक करें

https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx

न्यू इंडिया समाचार के बारे में लगातार अपडेट के लिए फॉलो करें: @NISPIBIndia

अंदर के पन्नों पर...

आवरण कथा

सतत विकास लक्ष्य के मानकों के आधार पर आइए जानते हैं कि केंद्र सरकार ने बीते एक दशक में अपनी योजना और नीतियों से शत-प्रतिशत लाभार्थी तक पहुंचने की पहल से कैसे नागरिकों की सुख-शांति, खुशहाली और समृद्धि को बना दिया है जन अधिकार... | 14-37

लीडरशिप कॉन्क्लेव

स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप (SOUL)

विकसित भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण कदम निभाएगा स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप | 48-49

निवेश सम्मेलन

भारत को लेकर दुनिया की निश्चितता का आधार भारत का तेज विकास

असम में एडवांटेज असम 2.0 और मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन | 40-44

समाचार सार | 4-5

मेलजोल से समृद्धि का पाठ पढ़ाती है भाषा
पीएम मोदी ने अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन को किया संबोधित | 38-39

बिहार की धरती से अन्नदाता को सम्मान
पीएम मोदी ने जारी की पीएम-किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त | 45-47

भारत और कतर : एक मजबूत साझेदारी की ओर बढ़ते कदम
कतर के अमीर अल-थानी का दो दिवसीय भारत दौरा | 50-51

व्यक्तित्व - दुलारी देवी
मिथिला पेंटिंग से रचा इतिहास | 52

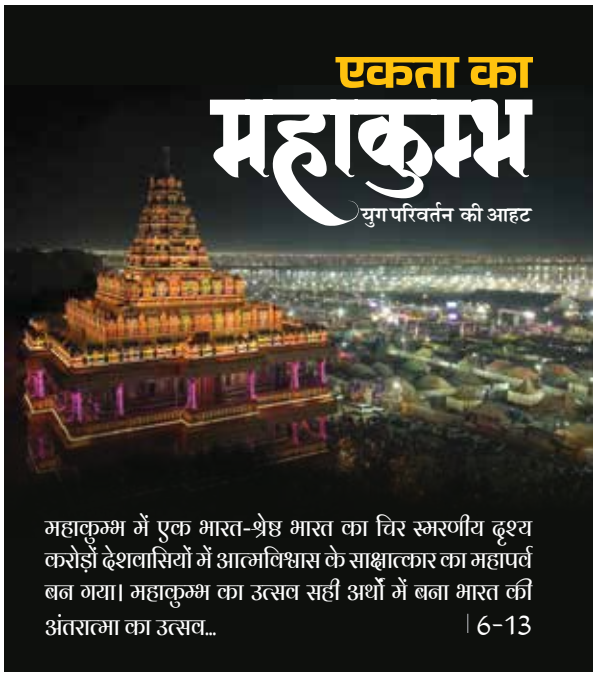

महाकुम्भ में एक भारत-श्रेष्ठ भारत का चिर स्मरणीय दृश्य करोड़ों देशवासियों में आत्मविश्वास के साक्षात्कार का महापर्व बन गया। महाकुम्भ का उत्सव सही अर्थों में बना भारत की अंतरात्मा का उत्सव... | 6-13

प्रकाशक और मुद्रकः योगेश कुमार बवेजा, महानिदेशक, सीबीसी (केंद्रीय संचार ब्यूरो)। **मुद्रणः** जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा. लि., बी-278, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020। **पत्राचार और ईमेल के लिए पताः** कमरा संख्या-316, नेशनल मीडिया सेंटर, रायसिना रोड, नई दिल्ली- 110001। **ईमेल-** response-nis@pib.gov.in आर. एन. आई. नंबर DELHIN/2020/78812

संपादक की कलम से...

एसडीजी मानकों के अनुरूप नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए एक दशक से प्रतिबद्ध सरकार

सादर नमस्कार।

सुधी पाठकों, भले दुनिया प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाता है लेकिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के मानकों के अनुरूप बीते एक दशक में अपने नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए निरंतर काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा यह मानना रहा है कि विकास तभी सशक्त और स्थिर होता है जब हर एक व्यक्ति को अवसर मिले और समाज के हर वर्ग तक खुशहाली पहुंचे। 17 सतत विकास लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 10-11 वर्ष में विशेष रूप से नीति और कार्यक्रमों की दिशा तय की है। सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप केंद्र सरकार के प्रयासों की बात करें तो गरीबी को जड़ से उखाड़ने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मिड-डे मील जैसी योजनाओं ने भारत में भूख और कुपोषण की समस्या को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आयुष्मान भारत योजना ने लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की तो शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने कई सुधार किए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान ने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया तो स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन ने स्वच्छता एवं जल प्रबंधन के साथ गरिमापूर्ण जीवन दिया है। भारत सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति की है तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के माध्यम से भारत को उत्पादन और रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का सुधार किया है तो भारत सरकार ने सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को खत्म करने के लिए कई योजनाएं शुरू कीं, जिनका उद्देश्य हर नागरिक को समान अवसर देना है। आधुनिक शहरी विकास योजनाओं ने भारत के शहरों को स्मार्ट और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं तो स्वच्छ ऊर्जा और सतत कृषि के क्षेत्र में कई पहल हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कई वैश्विक प्रयासों की शुरुआत की। समुद्र के संरक्षण के लिए मोदी सरकार ने कई कदम उठाए, जिनमें समुद्र तटों की सफाई और समुद्रों में मछलियों के जीवन के संरक्षण के लिए योजनाएं शामिल हैं।

साथ ही, भारत सरकार ने वन संरक्षण अभियान और वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। न्यायिक सुधार और कानून-व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक मंचों पर भारत का नेतृत्व किया है और विभिन्न देशों के साथ साझेदारी बढ़ाई, जिससे वैश्विक विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिली। सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप समान विकास और संतुष्टिकरण की अवधारणा ही इस बार हमारे अंक की आवरण कथा बनी है।

इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में पद्म श्री दुलारी देवी और प्रयागराज के महाकुंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आलेख इसमें शामिल है। साथ ही, पखवाड़े भर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अन्य कार्यक्रमों को भी इसमें शामिल किया गया है।

आप अपना सुझाव हमें भेजते रहें।

धीरेन्द्र

(धीरेन्द्र ओझा)

हिंदी, अंग्रेजी व अन्य 11 भाषाओं में उपलब्ध पत्रिका पढ़ें/डाउनलोड करें।
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

आपकी बात...

जन-जन तक पहुंचे न्यू इंडिया समाचार

हमें न्यू इंडिया समाचार पत्रिका पढ़ने को मिली। यह एक अच्छी पत्रिका है। यह पत्रिका हमें इतनी अच्छी लगी कि हम चाहते हैं कि यह जन-जन तक पहुंचे। हम चाहते हैं कि मेरे कॉलेज के पुस्तकालय में यह पत्रिका नियमित रूप से आए ताकि पाठक इसका लाभ ले सकें।

librarian@krcollege.net

संपूर्ण पत्रिका है न्यू इंडिया समाचार

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका की प्रति मुझे मिली जिसे पढ़ कर बहुत ही अच्छा लगा। यह एक संपूर्ण पत्रिका है। पत्रिका में स्टार्टअप युवा सामर्थ्य की पहचान शीर्षक वाली स्टोरी बेहतरीन लगी। ऐसी स्टोरी से युवाओं को स्टार्टअप करने की प्रेरणा मिलती है। युवा स्वावलंबी बन रहे हैं। देश को तरक्की की ओर ले जा रहे स्टार्टअप को पीएम मोदी बहुत महत्व दे रहे हैं।

अशोक कुमार
theharidwarreporter12@gmail.com

अच्छी लगती है न्यू इंडिया समाचार पत्रिका

मैंने गुजरात विश्वविद्यालय से पत्रकारिता और जनसंचार में पढ़ाई की है। मैंने न्यू इंडिया समाचार पत्रिका पढ़ी है। पत्रिकारिता के एक छात्र होने के नाते मुझे यह पत्रिका बहुत अच्छी लगी। गुजराती भाषा में यह पत्रिका पढ़ने में मुझे ज्यादा अच्छी लगती है।

डॉ. पार्थ पटेल
parth.patel30210@gmail.com

मलयालम और अंग्रेजी में पढ़ना पसंद है न्यू इंडिया समाचार

मुझे न्यू इंडिया समाचार पत्रिका पढ़ने में बहुत रुचि है। मुझे मलयालम भाषा में पत्रिका पढ़ने में ज्यादा अच्छी लगती है। अगर मलयालम भाषा में मुझे यह पत्रिका उपलब्ध नहीं हो पाती है तो मैं अंग्रेजी संस्करण में इसे पढ़ना पसंद करता हूं।

राजीव पी.एस.
rajeevsgindia@gmail.com

छात्रों के लिए एक अच्छी पत्रिका है न्यू इंडिया समाचार

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका मुझे काफी पसंद है क्योंकि इसके माध्यम से मैं भारत में होने वाले विकास के बारे में अवगत हो पाता हूं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह एक अच्छी पत्रिका है। हमें इस पत्रिका के सभी अंकों का बेसब्री से इंतजार रहता है।

जनार्दन देबता
janardandebata63@gmail.com

पत्राचार और ईमेल के लिए पता: कमरा संख्या-316,
नेशनल मीडिया सेंटर, रायसिना रोड, नई दिल्ली- 110001
ईमेल- response-nis@pib.gov.in

आकाशवाणी समाचार
Akashvani

न्यू इंडिया समाचार को आकाशवाणी पर सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें।

समाचार सार

बॉर्डर सुरक्षा और होगी मजबूत

केंद्र सरकार ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के लिए 10,200 करोड़ रुपये की लागत से गोला-बारूद खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। स्वदेशी पिनाका रॉकेट प्रणाली के माध्यम से टारगेट पर सटीक तरीके से भारी मात्रा में गोला-बारूद फेंका जा सकता है। इससे न सिर्फ दुश्मनों को आगे बढ़ने से रोका जा सकेगा, बल्कि उच्च सामरिक इलाकों पर भी जरूरत पड़ने पर टारगेट किया जा सकता है। सरकार की ओर से लिए गए इस निर्णय से देश की सैन्य ताकत को मजबूती मिलेगी साथ ही भारत की सीमा सुरक्षा भी मजबूत होगी। इसके अलावा शक्ति सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन के लिए भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ एक अनुबंध किया गया है।

वैश्विक बाजार में भारत के फार्मा सेक्टर की बढ़ी ताकत

भारत सरकार की नीतियों और प्रोडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) की वजह से पिछले कुछ वर्षों में देश के फार्मा सेक्टर में बहुत तेज गति से प्रगति हो रही है। भारत न सिर्फ फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि विश्व के कई देशों की जरूरतों को भी पूरा कर रहा है। बेन एंड कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2030 तक भारत का फार्मास्युटिकल सेक्टर वैश्विक बाजार में 5% की हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। वहीं, एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का फार्मा बाजार अगले पांच वर्ष में 2.4 गुना बढ़ोतरी के साथ 2030 तक 130 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगा। बता दें कि भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, वहीं वैश्विक वैक्सीन उत्पादन का 60% हिस्सा भारत पूरा करता है।

ईपीएफ में जमा राशि पर इस साल भी 8.25 फीसदी ब्याज

आप अगर कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में अंशदान करते हैं तो आपकी और आपके संस्थान की तरफ से जमा राशि पर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 8.25 फीसदी का ब्याज दर मिलेगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने पिछले वर्ष की तरह ही 2024-25 के लिए 8.25 फीसदी की ब्याज दर को जारी रखने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार द्वारा ब्याज दर को आधिकारिक रूप से अधिसूचित करने के बाद बाद ईपीएफओ ग्राहकों के खातों में ब्याज दर जमा करेगा। न्यासी बोर्ड ने कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा योजना में शामिल सदस्यों के परिवार को और अधिक लाभ एवं वित्तीय सहायता देने के लिए इसमें कुछ संशोधन किए हैं। सदस्य की मृत्यु एक साल निरंतर सेवा किए बिना होने पर 50 हजार रुपये का जीवन बीमा लाभ दिया जाएगा। अब अगर अंतिम अंशदान के 6 महीने के भीतर मृत्यु होती है तो इस योजना का लाभ दिया जाएगा। दो नौकरी के बीच 2 महीने तक के अंतराल को इस बीमा लाभ के मामले में अब निरंतर सेवा माना जाएगा। तीन संशोधन से सालाना करीब 20 हजार सदस्यों को लाभ होगा।

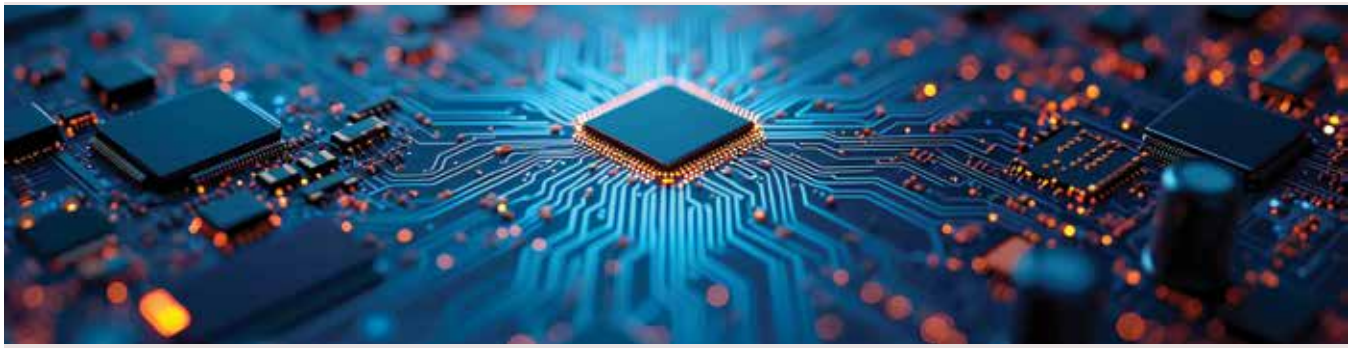

भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप

भारत सरकार ने पिछले कुछ समय से सेमीकंडक्टर पर विशेष ध्यान दिया है और देश में इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। देश में एक साथ सेमीकंडक्टर निर्माण की पांच इकाईयों पर काम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कहा कि वर्ष 2025 तक पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप तैयार हो जाएगी। सरकार ने उन्नत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 85,000 इंजीनियर को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। भारत वर्तमान में 5 लाख करोड़ रुपये का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात कर रहा है। इसमें मोबाइल (4 लाख करोड़ रुपये), लैपटॉप, सर्वर, दूरसंचार उपकरण (75,000 करोड़ रुपए) और रक्षा एवं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद भी शामिल है।

अब शहर के साथ गांवों में भी करीब 24 घंटे बिजली

केंद्र सरकार का लक्ष्य है, सभी को चौबीस घंटे बिजली मिले। इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है। पिछले 10 वर्ष में बिजली उत्पादन से लेकर बिजली आपूर्ति एवं बिजली बर्बादी रोकने में जबरदस्त सुधार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां वर्ष 2014 में प्रतिदिन औसत 12.5 घंटे बिजली आती थी, वहीं अब यह औसत 22.6 घंटे है। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में भी अब प्रतिदिन औसत 23.4 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2025 में बिजली ट्रांसमिशन लॉस में भी 8% की कमी आई है। गांव-गांव तक 24 घंटे बिजली आपूर्ति होने के कारण ही सरकार ने वर्ष 2030 तक देश में एक लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का भी निर्णय लिया है।

खेती-किसानी
में महाशक्ति बनता भारत

कृषि क्षेत्र को लेकर बीते एक दशक में केंद्र सरकार की मजबूत नीतियों का परिणाम किसानों की आय में बढ़ोतरी के साथ-साथ रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन के रूप में सामने आया है। देश में विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना के तहत अभी तक किसानों को जहां 1.72 लाख करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं तो वहीं पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 3.70 लाख करोड़ रुपये उनके खातों में भेजे गए हैं। किसानों की फसल को सुरक्षित रखने के लिए 9,750 मीट्रिक टन क्षमता के स्टोरेज की व्यवस्था की गई है। सरकार किसानों को सस्ती दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए बड़ी मात्रा में सब्सिडी दे रही है। किसानों को दी जा रही सुविधा से ही वर्ष 2023-24 में अभी तक का सबसे ज्यादा 332 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ।

एकता का महाकुम्भ

युग परिवर्तन की आहट

प्रयागराज महाकुम्भ में हमने देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार किया। आज पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं है। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है।

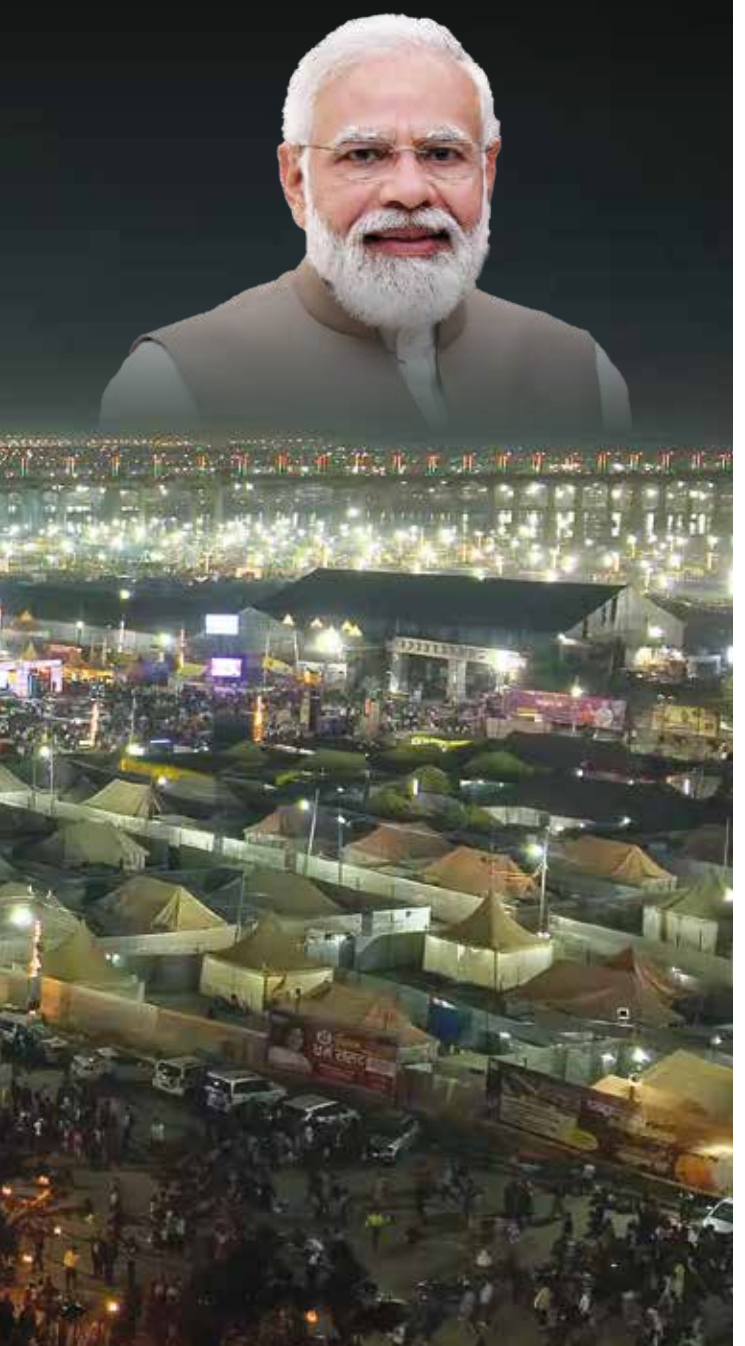

अद्भुत, अलौकिक... जैसे शब्द भी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर- महाकुम्भ के सफलतम आयोजन के लिए कम ही होगा। समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोग इस महाकुम्भ में एक हो गए। यह एक भारत-श्रेष्ठ भारत का चिर स्मरणीय दृश्य करोड़ों देशवासियों में आत्मविश्वास के साक्षात्कार का महापर्व बन गया। महाकुम्भ का उत्सव सही अर्थों में भारत की अंतरात्मा का उत्सव बन गया। प्रयागराज में एकता के महाकुम्भ में पूरे 45 दिन तक जिस प्रकार 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ, एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ी, वो अभिभूत करता है।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंत:करण से निकली अनुभूति इस महाकुम्भ के विराट संदेश का भी साक्षात्कार कराती है। वे कहते हैं, "एकता के महाकुम्भ को सफल बनाने के लिए देशवासियों के परिश्रम, उनके प्रयास, उनके संकल्प से अभिभूत मैं द्वादश ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग, श्री सोमनाथ के दर्शन करने जाऊंगा। मैं श्रद्धा रूपी संकल्प पुष्प को समर्पित करते हुए हर भारतीय के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं कामना करूंगा कि देशवासियों में एकता की ये अविरल धारा, ऐसे ही बहती रहे।" प्रयागराज महाकुम्भ के पूर्ण होने पर जो विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में आए, उसे उन्होंने कुछ इस तरह कलमबद्ध किया है...

महाकुम्भ संपन्न हुआ... एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की

मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है, जैसा हमने 13 जनवरी के बाद से प्रयागराज में एकता के महाकुम्भ में देखा।

22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मैंने देवभक्ति से देशभक्ति की बात कही थी। प्रयागराज में महाकुम्भ के दौरान सभी देवी-देवता जुटे, संत-महात्मा जुटे, बाल-वृद्ध जुटे, महिलाएं-युवा जुटे और हमने देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार किया। ये महाकुम्भ एकता का महाकुम्भ था, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ गई थी।

तीर्थराज प्रयाग के इसी क्षेत्र में एकता, समरसता और प्रेम का पवित्र क्षेत्र श्रृंगवेरपुर भी है, जहां प्रभु श्रीराम और निषादराज का मिलन हुआ था। उनके मिलन का वो प्रसंग भी हमारे इतिहास में भक्ति और सद्भाव के संगम की तरह ही है। प्रयागराज का ये तीर्थ आज भी हमें एकता और समरसता की प्रेरणा देता है।

बीते 45 दिन, प्रतिदिन, मैंने देखा, कैसे देश के कोने-कोने से लाखों-लाख लोग संगम तट की ओर बढ़े जा रहे हैं। संगम पर स्नान की भावनाओं का ज्वार, लगातार बढ़ता ही रहा। हर श्रद्धालु बस एक ही धुन में था- संगम में स्नान। मां गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी हर श्रद्धालु को उमंग, ऊर्जा और विश्वास के भाव से भर रही थी।

प्रयागराज में हुआ महाकुम्भ का ये आयोजन, आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय बना है। आज पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है।

पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक नदी तट पर, त्रिवेणी संगम पर इतनी बड़ी संख्या में करोड़ों लोग जुटे। इन करोड़ों लोगों को न औपचारिक निमंत्रण था, न ही किस समय पहुंचना है, उसकी कोई पूर्व सूचना थी। बस, लोग महाकुम्भ चल पड़े... और पवित्र संगम में डुबकी लगाकर धन्य हो गए।

मैं वो तस्वीरें भूल नहीं सकता... स्नान के बाद असीम आनंद और संतोष से भरे वो चेहरे नहीं भूल सकता। महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, हमारे दिव्यांगजन हों, जिससे जो बन पड़ा, वो साधन करके संगम तक पहुंचा। और मेरे लिए ये देखना बहुत ही सुखद रहा कि बहुत बड़ी संख्या में भारत की आज की युवा पीढ़ी प्रयागराज पहुंची।

भारत के युवाओं का इस तरह महाकुम्भ में हिस्सा लेने के लिए आगे आना, एक बहुत बड़ा संदेश है। इससे ये विश्वास दृढ़ होता है कि भारत की युवा पीढ़ी हमारे संस्कार और संस्कृति की वाहक है और इसे आगे ले जाने का दायित्व समझती है और इसे लेकर संकल्पित भी है, समर्पित भी है।

इस महाकुम्भ में प्रयागराज पहुंचने वालों की संख्या ने निश्चित तौर पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन इस महाकुम्भ में हमने ये भी देखा कि जो प्रयाग नहीं पहुंच पाए, वो भी इस आयोजन से भाव-विभोर होकर जुड़े। कुम्भ से लौटते हुए जो लोग त्रिवेणी तीर्थ

अपने साथ लेकर गए, उस जल की कुछ बूंदों ने भी करोड़ों भक्तों को कुम्भ स्नान जैसा ही पुण्य दिया। कितने ही लोगों का कुम्भ से वापसी के बाद गांव-गांव में जो सत्कार हुआ, जिस तरह पूरे समाज ने उनके प्रति श्रद्धा से सिर झुकाया, वो अविस्मरणीय है।

ये कुछ ऐसा हुआ है, जो बीते कुछ दशकों में पहले कभी नहीं हुआ। ये कुछ ऐसा हुआ है, जो आने वाली कई-कई शताब्दियों की एक नींव रख गया है। प्रयागराज में जितनी कल्पना की गई थी, उससे कहीं अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इसकी एक वजह यह भी थी कि प्रशासन ने भी पुराने कुम्भ के अनुभवों को देखते हुए ही अंदाजा लगाया था। लेकिन अमेरिका की आबादी के करीब दोगुने लोगों ने एकता के महाकुम्भ में हिस्सा लिया, डुबकी लगाई।

आध्यात्मिक क्षेत्र में रिसर्च करने वाले लोग करोड़ों भारतवासियों के इस उत्साह पर अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि अपनी विरासत पर गौरव करने वाला भारत अब एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं मानता हूं, ये युग परिवर्तन की वो आहट है, जो भारत का नया भविष्य लिखने जा रही है।

साथियों,

महाकुम्भ की इस परंपरा से, हजारों वर्षों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को बल मिलता रहा है। हर पूर्णकुम्भ में समाज की उस समय की परिस्थितियों पर ऋषि-मुनियों, विद्वत् जनों द्वारा 45 दिन तक मंथन होता था। इस मंथन में देश को, समाज को नए दिशा-निर्देश मिलते थे।

इसके बाद हर 6 वर्ष में अर्धकुम्भ में परिस्थितियों और दिशा-निर्देशों

जहां **आस्था** के साथ है **विज्ञान**

जहां **संस्कृति** के साथ है **सामाजिकता**

जहां **श्रद्धा** के साथ है **सामूहिकता** और विश्व के लिए है **वसुधैव कुटुंबकम्** का संदेश...

144 वर्ष के बाद होने वाले महाकुम्भ में ऋषि-मुनियों द्वारा, उस समय-काल और परिस्थितियों को देखते हुए नए संदेश भी दिए जाते थे। इस बार भारत ने अपनी विकासयात्रा के नए अध्याय का संदेश दिया है। यह संदेश है- विकसित भारत का।

> मैं मां गंगा... मां यमुना... मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि हे मां हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। जनता जनार्दन, जो मेरे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी कुछ कमी रह गई हो तो मैं क्षमाप्रार्थी हूं।

की समीक्षा होती थी। 12 पूर्णकुम्भ होते-होते, यानी 144 साल के अंतराल पर जो दिशा-निर्देश, जो परंपराएं पुरानी पड़ चुकी होती थीं, उन्हें त्याग दिया जाता था, आधुनिकता को स्वीकार किया जाता था और युगानुकूल परिवर्तन करके नए सिरे से नई परंपराओं को गढ़ा जाता था।

144 वर्ष के बाद होने वाले महाकुम्भ में ऋषि-मुनियों द्वारा, उस समय-काल और परिस्थितियों को देखते हुए नए संदेश भी दिए जाते थे। अब इस बार 144 वर्ष के बाद पड़े इस तरह के पूर्ण महाकुम्भ ने भी हमें भारत की विकासयात्रा के नए अध्याय का संदेश दिया है। ये संदेश है- विकसित भारत का।

जिस तरह एकता के महाकुम्भ में हर श्रद्धालु, चाहे वो गरीब हों या संपन्न हों, बाल हो या वृद्ध हो, देश से आया हो या विदेश से आया हो, गांव का हो या शहर का हो, पूर्व से हो या पश्चिम से हो, उत्तर से हो दक्षिण से हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी विचारधारा का हो, सब एक महायज्ञ के लिए एकता के महाकुम्भ में एक हो गए। एक भारत-श्रेष्ठ भारत का ये चिर स्मरणीय दृश्य, करोड़ों देशवासियों में आत्मविश्वास के साक्षात्कार का महापर्व बन गया। अब इसी तरह हमें एक होकर विकसित भारत के महायज्ञ के लिए जुट जाना है।

साथियों,

आज मुझे वो प्रसंग भी याद आ रहा है जब बालक रूप में श्रीकृष्ण ने माता यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। वैसे ही इस महाकुम्भ में भारतवासियों ने और विश्व ने भारत के सामर्थ्य के विराट स्वरूप के दर्शन किए हैं। हमें अब इसी आत्मविश्वास से एक निष्ठ होकर, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है।

भारत की ये एक ऐसी शक्ति है, जिसके बारे में भक्ति आंदोलन में हमारे संतों ने राष्ट्र के हर कोने में अलख जगाई थी। विवेकानंद हों या श्री अरबिंदो हों, हर किसी ने हमें इसके बारे में जागरूक किया

था। इसकी अनुभूति गांधी जी ने भी आजादी के आंदोलन के समय की थी। आजादी के बाद भारत की इस शक्ति के विराट स्वरूप को यदि हमने जाना होता, और इस शक्ति को सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की ओर मोड़ा होता, तो ये गुलामी के प्रभावों से बाहर निकलते भारत की बहुत बड़ी शक्ति बन जाती। लेकिन हम तब ये नहीं कर पाए। अब मुझे संतोष है, खुशी है कि जनता जनार्दन की यही शक्ति, विकसित भारत के लिए एकजुट हो रही है।

वेद से विवेकानंद तक और उपनिषद से उपग्रह तक, भारत की महान परंपराओं ने इस राष्ट्र को गढ़ा है। मेरी कामना है, एक नागरिक के नाते, अनन्य भक्ति भाव से, अपने पूर्वजों का, हमारे ऋषि-मुनियों का पुण्य स्मरण करते हुए, एकता के महाकुम्भ से हम नई प्रेरणा लेते हुए, नए संकल्पों को साथ लेकर चलें। हम एकता के महामंत्र को जीवन मंत्र बनाएं, देश सेवा में ही देव सेवा, जीव सेवा में ही शिव सेवा के भाव से स्वयं को समर्पित करें।

साथियों,

जब मैं काशी चुनाव के लिए गया था, तो मेरे अंतरमन के भाव शब्दों में प्रकट हुए थे, और मैंने कहा था- मां गंगा ने मुझे बुलाया है। इसमें एक दायित्व बोध भी था, हमारी मां स्वरूपा नदियों की पवित्रता को लेकर, स्वच्छता को लेकर। प्रयागराज में भी गंगा-यमुना-सरस्वती के संगम पर मेरा ये संकल्प और दृढ़ हुआ है। गंगा जी, यमुना जी, हमारी नदियों की स्वच्छता हमारी जीवन यात्रा से जुड़ी है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नदी चाहे छोटी हो या बड़ी, हर नदी को जीवनदायिनी मां का प्रतिरूप मानते हुए हम अपने यहां सुविधा के अनुसार, नदी उत्सव जरूर मनाएं। ये एकता का महाकुम्भ हमें इस बात की प्रेरणा देकर गया है कि हम अपनी नदियों को निरंतर स्वच्छ रखें, इस अभियान को निरंतर मजबूत करते रहें।

मैं जानता हूं, इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूं मां गंगा से... मां यमुना से... मां सरस्वती से...हे मां हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा...। जनता जनार्दन, जो मेरे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो, तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमाप्रार्थी हूं।

साथियों,

श्रद्धा से भरे जो करोड़ों लोग प्रयाग पहुंचकर इस एकता के महाकुम्भ का हिस्सा बने, उनकी सेवा का दायित्व भी श्रद्धा के सामर्थ्य से ही पूरा हुआ है। यूपी का सांसद होने के नाते मैं गर्व से कह सकता हूं कि योगी जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर, इस एकता के महाकुम्भ को सफल बनाया। केंद्र हो या राज्य हो, यहां न कोई शासक था, न कोई प्रशासक था,

पीएम मोदी ने 2 मार्च को श्री सोमनाथ भगवान के दर्शन किए।

हर कोई श्रद्धा भाव से भरा सेवक था। हमारे सफाईकर्मी, हमारे पुलिसकर्मी, नाविक साथी, वाहन चालक, भोजन बनाने वाले, सभी ने पूरी श्रद्धा और सेवा भाव से निरंतर काम करके इस महाकुम्भ को सफल बनाया। विशेषकर, प्रयागराज के निवासियों ने इन 45 दिनों में तमाम परेशानियों को उठाकर भी जिस तरह श्रद्धालुओं की सेवा की है, वह अतुलनीय है। मैं प्रयागराज के सभी निवासियों का, यूपी की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं।

साथियों,

महाकुम्भ के दृश्यों को देखकर, बहुत प्रारंभ से ही मेरे मन में जो भाव जगे, जो पिछले 45 दिनों में और अधिक पुष्ट हुए हैं, राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य को लेकर मेरी आस्था, अनेक गुना मजबूत हुई है। 140 करोड़ देशवासियों ने जिस तरह प्रयागराज में एकता के महाकुम्भ को आज के विश्व की एक महान पहचान बना दिया, वो अद्भुत है।

देशवासियों के इस परिश्रम से, उनके प्रयास से, उनके संकल्प से अभीभूत मैं जल्द ही द्वादश ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग, श्री सोमनाथ के दर्शन करने जाऊंगा और श्रद्धा रूपी संकल्प पुष्प को समर्पित करते हुए हर भारतीय के लिए प्रार्थना करूंगा। **(अपने इस संकल्प को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च के दिन सोमनाथ के दर्शन कर पूरा किया। उन्होंने कहा कि मैंने सभी देशवासियों की ओर से एकता के महाकुंभ की सफल सिद्धि को श्री सोमनाथ भगवान के चरणों में समर्पित किया।)**

महाकुम्भ का स्थूल स्वरूप महाशिवरात्रि को पूर्णता प्राप्त कर गया है। लेकिन मुझे विश्वास है, मां गंगा की अविरल धारा की तरह, महाकुम्भ की आध्यात्मिक चेतना की धारा और एकता की धारा निरंतर बहती रहेगी। ■

विशालता- विविधता का महाकुम्भ

लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेक अखाड़े महाकुम्भ का हिस्सा बनते हैं। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, जैसा महाकुम्भ 2025 में देखने को मिला। अनेकता में एकता, विशालता और विविधता के 45 दिन के महाकुम्भ में अनुमान से 21 करोड़ अधिक श्रद्धालु पहुंचे। न सिर्फ संख्या अपने आप में रिकॉर्ड रही बल्कि दो साफ-सफाई और एक हैंड प्रिंट पेंटिंग का विश्व रिकॉर्ड भी संगम के तट पर बना...

यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त, कुम्भ मेला भारत की स्थायी परंपराओं का प्रतीक है। पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि यानी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक (45 दिन) चले महाकुम्भ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा तट पर जुटे और डुबकी लगाई। यह दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है। यह संख्या अमेरिका की आबादी का करीब-करीब दोगुना है। इतना ही नहीं संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दुनिया के 193 देशों की आबादी से अधिक है। सिर्फ भारत और चीन की आबादी ही महाकुम्भ में आए श्रद्धालुओं से अधिक है हालांकि इसका कोई विश्व रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ। महाकुम्भ में 80 से अधिक देशों के लोग भी आयोजन के भागीदार बने।

महाकुम्भ समापन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आस्था का इतना बड़ा समागम दुनिया में कहीं नहीं हुआ। कोई अपहरण, लूट, छेड़छाड़ या दुष्कर्म की घटना नहीं हुई। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालु यहां थे, दुखद घटना घटी थी, उन सभी परिवारजनों के प्रति संवेदना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस शहर में 20-25 लाख लोग रहते हैं, उस शहर में अचानक 5 से 8 करोड़ लोग एक दिन में आ जाएं तो क्या स्थिति होगी। जिस घर में 5 लोग रहते हैं, अचानक 10 लोग आ जाएं तो क्या हालत होगी।

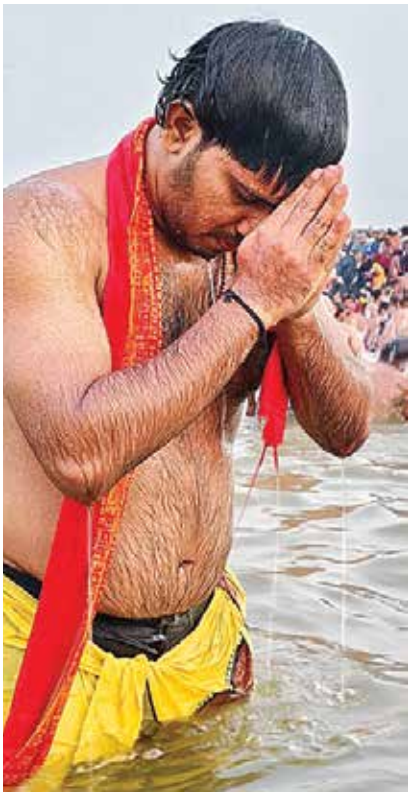

अनुमान था 45 करोड़ का, पहुंचे 66 करोड़+

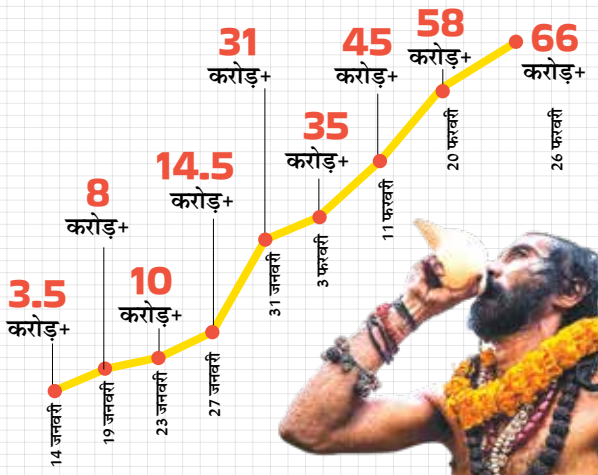

80

से अधिक देशों के लोग भी आयोजन के भागीदार बने महाकुम्भ में

डिजिटल महाकुंभ के साक्षी बने लोग

महाकुम्भ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं को अपने गंतव्य तक पहुंचने में किसी तरह की दिक्कत न हो इसलिए डिजिटल नैविगेशन की मदद से अलग अलग घाट, मंदिर और अखाड़े तक पहुंचाने का सिस्टम तैयार किया गया। साथ में पहली बार एआई चैटबोट का इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से 11 भारतीय भाषा में कुम्भ से जुड़ी जानकारी आसानी से श्रद्धालुओं को मिल सकी।

3 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' बने इस बार प्रयागराज महाकुम्भ में

- **रिकॉर्ड कुम्भ मेला में गंगा की सफाई का**
  दुनिया में किसी भी नदी की सफाई के लिए सबसे ज्यादा 329 जगह पर सबसे बड़ा नदी स्वच्छता अभियान चलाया गया।
- **रिकॉर्ड झाड़ू लगाने का**
  19 हजार सफाईकर्मियों व कार्यकर्ताओं ने महाकुम्भ मेला क्षेत्र में एक साथ झाड़ू लगाई। पिछला रिकॉर्ड 10 हजार लोगों का था।
- **रिकॉर्ड हैंड प्रिंट पेंटिंग का**
  8 घंटे में 10,102 लोगों ने अपने हाथ की छाप लगाकर चित्रकारी की। पिछला रिकॉर्ड 7660 लोगों का था।

- अर्धसैनिक बल सहित 50 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात रहे, 14,000 होमगार्ड भी शामिल। 2,750 एआई-आधारित सीसीटीवी कैमरा कर रहे थे निगरानी।
- 16 हजार से अधिक ट्रेन चलाई गईं। करीब 4 से 5 करोड़ श्रद्धालुओं को रेलवे महाकुम्भ के लिए लेकर आया।
- 3,050 बसें निरंतर चलाई गईं जबकि 12 फरवरी को 1,200 अतिरिक्त बसें चलाई गईं।
- 106 साल में पहली बार एक दिन में प्रयागराज एयरपोर्ट पर रात्रिकालीन उड़ान शुरू करके 24/7 एयर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई। एक दिन में 5,000 यात्री ने भी पहली बार यहां से यात्रा की।
- 10,200 सफाई कर्मचारी और 1,800 गंगा सेवादूत रहे तैनात।

विशेष स्नानः श्रद्धालुओं का महाकुम्भ

पौष पूर्णिमा	13 जनवरी	1.5 करोड़+
मकर संक्रांति	14 जनवरी	3.5 करोड़+
मौनी अमावस्या	29 जनवरी	5 करोड़+
बसंत पंचमी	3 फरवरी	2.33 करोड़+
माघी पूर्णिमा	12 फरवरी	2 करोड़+
महाशिवरात्रि	26 फरवरी	1.3 करोड़+

लेकिन, प्रयागराज के लोगों ने हंसी-खुशी संभाला। प्रयागराज से प्रेरित होकर पूरे प्रदेश ने श्रद्धालुओं और संतों का स्वागत किया।

महाकुम्भ के दौरान काशी विश्वनाथ और विंध्यवासिनी का एक सर्किट बना तो अयोध्या और गोरखपुर का दूसरा सर्किट बना, वहीं प्रयागराज से श्रृंग्वेरपुर होते हुए लखनऊ और नैमिषारण्य का तीसरा सर्किट एवं प्रयागराज से लालापुर-राजापुर और चित्रकूट का चौथा सर्किट और प्रयागराज से वृंदावन का पांचवा सर्किट बना। फरवरी में प्रतिदिन औसतन पांच से छह लाख श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुम्भ के कारण बाबा विश्वनाथ धाम, अयोध्या, वृंदावन में श्रद्धालुओं की बढ़ी संख्या के साथ ही अर्थव्यवस्था के विस्तार का जिक्र करते हुए धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं के दोहन की बात कही। व्यापार जगत से जुड़े संगठनों ने इस महाकुम्भ के 45 दिन में 3.25 लाख करोड़ रुपये के व्यापार का अनुमान लगाया है।

संतुष्टिकरण का मंत्र
खुशहाली की ओर कदम

अगर आप खुशहाल जीवन चाहते हैं तो इसे एक लक्ष्य से बांधें। संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे यानी खुश रहने का दिवस घोषित किया, जिसे 2013 से मनाया जाता है। वर्ष 2014 से भारत में एक नई शुरुआत हुई जिसने 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' का मंत्र अपनाकर सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के 17 मानक पर काम शुरू किया। अपनी रणनीति में जनता की सुख और खुशहाली को ध्यान में रखकर बीते 10-11 वर्ष में केंद्र सरकार ने 140 करोड़ नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप लगातार काम किया है, जिससे बदल रहा है सामाजिक-आर्थिक परिवेश और बढ़ने लगे हैं विकसित भारत की ओर कदम...

सतत विकास लक्ष्य के मानकों के आधार पर आइए जानते हैं कि केंद्र सरकार ने बीते एक दशक में अपनी योजना और नीतियों से शत-प्रतिशत लाभार्थी तक पहुंचने की पहल से कैसे नागरिकों की सुख-शांति, खुशहाली-समृद्धि को बना दिया है जन अधिकार...

पिछले एक दशक में भारत में 4 करोड़ से अधिक परिवारों को घर उपलब्ध कराया गया है। पिछले पांच सालों में, 12 करोड़ से अधिक घरों तक साफ पानी पहुंचाया गया है। 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध कराया गया है। और 11.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों के लिए शौचालय बनाए गए हैं। सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में यह भारत की प्रतिबद्धता है।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

जनशक्ति सर्वोपरि। जब यह दृष्टिकोण बन जाता है तो परिणाम भी उसके अनुरूप दिखने लगते हैं। बीते एक दशक में भारत उन परिवर्तनकारी परिणामों का साक्षी बना है, जिसकी उम्मीद दुनिया और संयुक्त राष्ट्र से निर्धारित सतत विकास लक्ष्य करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा यह मानना रहा है कि विकास तभी सशक्त और स्थिर होता है, जब हर एक व्यक्ति को अवसर मिले और खुशहाली समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। 17 सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने नीति और कार्यक्रमों की दिशा तय की थी, जिनका उद्देश्य न केवल आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय समृद्धि भी था। इन लक्ष्यों में से कुछ प्रमुख हैं- गरीबी उन्मूलन, शून्य भूख, अच्छे स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छ ऊर्जा, जो पूरी दुनिया के लिए जरूरी हैं। केंद्र सरकार ने इन सभी पहलुओं पर ध्यान दिया और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनका उद्देश्य लोगों के जीवन

को सरल, समृद्ध और खुशहाल बनाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए गरीब, महिला, बच्चे और बुजुर्ग के लिए ऐसी कई योजनाएं शुरू की गईं हैं, जिनका सीधा असर उनके जीवन की गुणवत्ता पर पड़ा है। इतना ही नहीं, जब कोविड जैसी वैश्विक आपदा आई तो केंद्र सरकार ने 'जान है तो जहान है' का मंत्र देकर पहले नागरिकों को सुरक्षित रखने की दिशा में कदम उठाए। यह केंद्र सरकार की प्राथमिकता और मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है।

सबका साथ-सबका विकास

'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के आदर्श वाक्य से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन में एक आदर्श बदलाव की शुरुआत की है जिससे समावेशी, विकासोन्मुख और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अंत्योदय के उद्देश्य को साकार करने और समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजना और पहल का लाभ सुनिश्चित करने के लिए स्पीड और स्केल पर काम किया। यही कारण है कि प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने इस बात को माना कि भारत रिकॉर्ड गति से गरीबी को खत्म कर रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इसका श्रेय केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए लिए गए विभिन्न पहल और निर्णयों को जाता है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम 'आयुष्मान भारत' सफलतापूर्वक चला रहा है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित स्वास्थ्य पत्रिकाओं में से एक लांसेट ने आयुष्मान भारत की सराहना करते हुए कहा है कि यह योजना भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े असंतोष को दूर कर रही है। पत्रिका ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्राथमिकता देने के लिए पीएम मोदी के प्रयासों की भी सराहना की।

आवास, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ और स्वच्छता गरिमामय जीवन के लिए अनिवार्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक ठोस योजना और एक निश्चित समय सीमा तय कर पहल की। गरीबों को वित्तीय धारा से जोड़ने के लिए पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय का बैंक खाता खोलना था। इन खातों ने न केवल गरीबों को बैंक से जोड़ा, बल्कि सशक्तीकरण के अन्य रास्ते भी खोले हैं। जन-धन से एक कदम आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को बीमा और पेंशन कवर देकर जन सुरक्षा पर जोर दिया। जैम ट्रिनिटी (जन धन-आधार-मोबाइल) ने बिचौलियों को समाप्त कर दिया है तो प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शिता और गति

> आजादी के बाद से ही हम भारत से गरीबी हटाने के सपने को लेकर चल रहे हैं। हमने गरीबों को सशक्त करके गरीबी हटाने का रास्ता चुना। हमने शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता दी है। आज गरीबी पर हमारे हमले में विकास की पारंपरिक योजनाओं का विस्तार शामिल है, लेकिन हमने समावेशन व सशक्तीकरण के एक नए युग की भी शुरूआत की और दूर के सपनों को तत्काल संभावनाओं में बदल दिया है।
>
> - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

भी सुनिश्चित की है। 2016 में गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना करोड़ों महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान लाने में महत्वपूर्ण साबित हुई है तो सौभाग्य योजना के जरिए आजादी के 70 साल बाद भी बिजली से वंचित रहे 18,000 गांव तक रोशनी पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी का

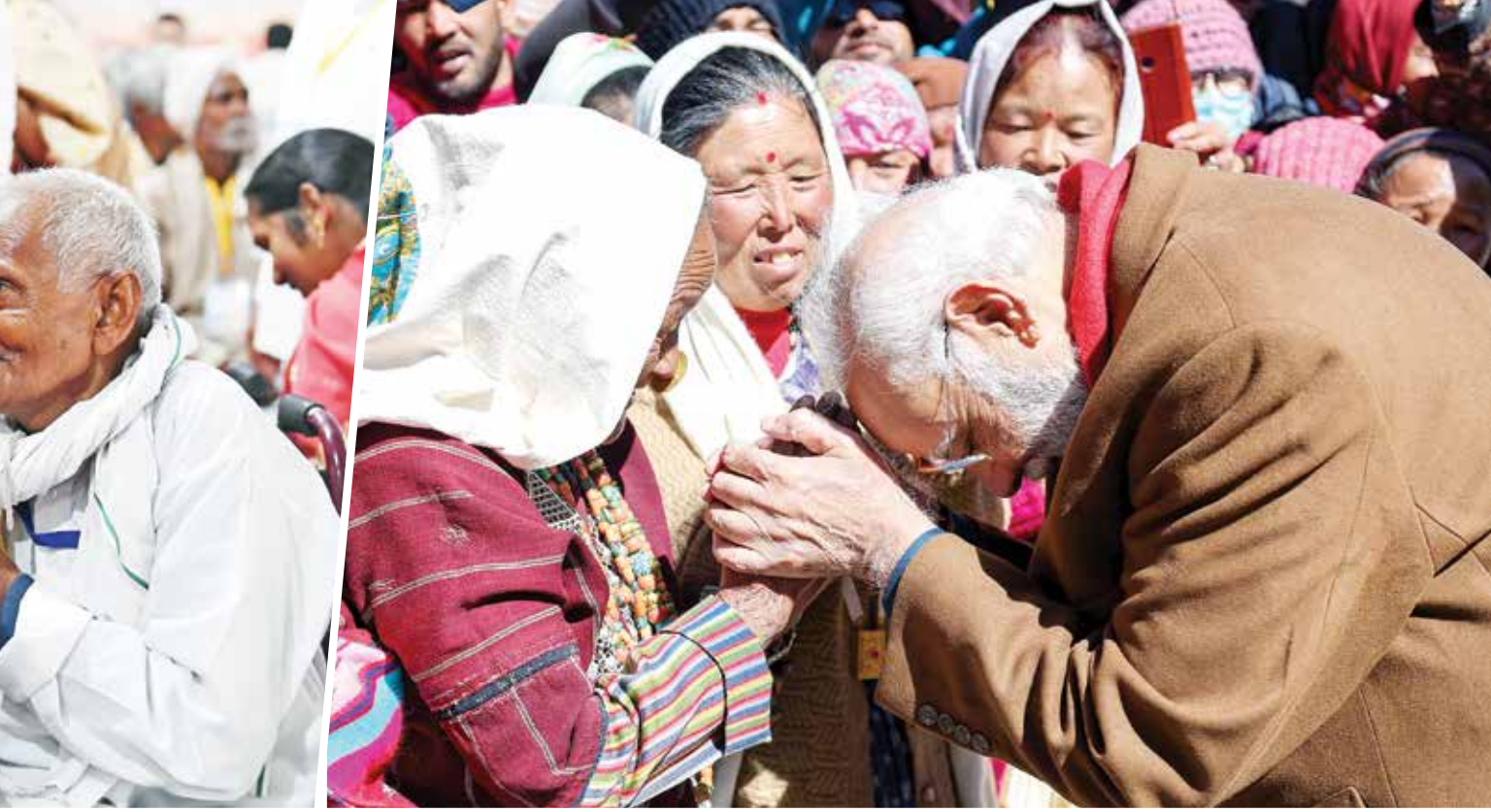

भारत के प्रदर्शन में लगातार सुधार

वर्ष 2023-24 में भारत का समग्र एसडीजी स्कोर 71 हो गया, जो वर्ष 2020-21 में 66 और वर्ष 2018 में 57 था। केरल और उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे, जिनमें से प्रत्येक को 79 अंक मिले। 32 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश (**UT**) अग्रणी श्रेणी में हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश सहित 10 नए प्रवेशक राज्य शामिल हैं।

लक्ष्य है कि कोई भी भारतीय बेघर नहीं होना चाहिए और इस विजन को साकार करने के लिए 2014 और 2024 के बीच पीएम आवास योजना के तहत 4.53 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी गई। जून 2024 में तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता संभालने के बाद पहली कैबिनेट के निर्णयों में से एक कदम 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना था, जो देश की आवास आवश्यकताओं का समाधान करने और प्रत्येक नागरिक के लिए गरिमा और गुणवत्तापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

इसी तरह कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीब है। 2019 के अंतरिम बजट के दौरान सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में एक मौद्रिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। 24 फरवरी 2019 को योजना के शुरू होने के बाद लगभग हर 3 महीने में नियमित रूप से किस्तों का भुगतान किया जा रहा है। सॉयल हेल्थ कार्ड, बेहतर बाजारों के लिए ई-NAM और सिंचाई पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने जैसी किसान कल्याण की दिशा में विभिन्न पहलों की शुरूआत की गई है। 30 मई 2019 को पीएम मोदी ने जल संसाधनों से संबंधित सभी पहलुओं की देखरेख करने के लिए नया जल शक्ति मंत्रालय बनाकर एक बड़ा वादा पूरा किया।

2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 'स्वच्छ भारत मिशन' का शुभारंभ किया। इस जन आंदोलन का बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक प्रभाव पड़ा है। स्वच्छता कवरेज 2014 में 38% से बढ़कर 2019 में 100% हो गया है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है। स्वच्छ गंगा के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वच्छ भारत मिशन की सराहना की और कहा कि इससे 3 लाख लोगों की जान बच सकती है।

भारत सरकार का मानना है कि परिवहन, परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन है। इसीलिए भारत सरकार हाई-वे, रेलवे, आई-वे और वॉटर-वे के रूप में अगली पीढ़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए काम कर रही है। उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना ने उड्डयन क्षेत्र को लोगों के अधिक अनुकूल बनाया है और कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया है। पीएम मोदी ने भारत को अंतरराष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस में बदलने के लिए 'मेक इन इंडिया' पहल शुरू की। इस प्रयास से परिवर्तनकारी परिणाम सामने आए हैं।

पीएम मोदी को पर्यावरण से जुड़े मुद्दों से गहरा लगाव है। उन्होंने हमेशा से माना है कि एक क्लीन और ग्रीन प्लेनेट बनाने के लिए काम करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन से एक कदम आगे बढ़कर पीएम मोदी ने क्लाइमेट जस्टिस के बारे में बात की है। 2018 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए थे। यह गठबंधन एक बेहतर ग्रह के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का एक अभिनव प्रयास है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनके प्रयासों को देखते हुए पीएम मोदी को संयुक्त राष्ट्र के 'चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड' से सम्मानित किया गया।

प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से पीएम मोदी ने नागरिकों के लिए न्याय को हमेशा प्राथमिकता दी है। गुजरात में लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए उन्होंने शाम की अदालतों की शुरुआत की थी तो केंद्र में उन्होंने प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) शुरू किया जो विकास में देरी कर रहे लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए एक कदम है।

...ताकि कोई पीछे न छूटे

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की सोच को साकार करते हुए केंद्र सरकार का लक्ष्य 100% सैचुरेशन यानी शत् प्रतिशत लाभार्थी तक पहुंचना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने संतुष्टीकरण का मार्ग चुना है, जहां हर समाज हर वर्ग के लोगों को बिना भेदभाव के जो उसके हक का है वह उसको मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, "मेरे हिसाब से जब मैं 100% सैचुरेशन की बात करता हूं तो यह है संतुष्टिकरण। उसका मतलब है- असल में सामाजिक न्याय। यह असल में सेकुलरिज्म है और असल में यह संविधान का सम्मान है।"

पिछले 10 साल में सेल्फ हेल्प ग्रुप में अब तक 10 करोड़ नई महिलाएं इसमें जुड़ी हैं। यह महिलाएं वंचित परिवार और ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। समाज के अंतिम पायदान पर बैठी इन महिलाओं का सामर्थ्य बढ़ा, उनका सामाजिक स्तर भी ऊपर उठा और

"हम हर योजना के पीछे लगे हैं, 100% सैचुरेशन... यानी शत प्रतिशत उसको लागू करें, उसके जो भी लाभार्थी हैं, वो उसमें छूट न जाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिसका हक है, उसको मिलना चाहिए। 1 रूपये में 15 पैसे वाला खेल अब नहीं चल सकता। देश को विकसित भारत बनाने के लिए तुष्टिकरण से मुक्ति पाना होगा, हमने रास्ता चुना है संतुष्टीकरण, तुष्टिकरण नहीं। हम उस रास्ते पर चले हैं। हर समाज हर वर्ग के लोगों को बिना भेदभाव के उसका हक मिलना चाहिए यह है संतुष्टिकरण।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

सरकार ने इनकी मदद 20 लाख रुपये तक बढ़ा दी है, ताकि वो इस काम को आगे बढ़ा सकें। उनकी कार्य क्षमता बढ़े, उसका स्केल बढ़े, उस दिशा में प्रयास हो रहा है। जिसका आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हो रहा है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त किए बिना विकसित भारत का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी पहलुओं को छूने का प्रयास किया जा रहा है। बीते एक दशक में खेती के बजट में 10 गुना वृद्धि की गई है। किसानों को सस्ती खाद मिले इस एक काम के लिए पिछले 10 साल में 12 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से करीब साढे तीन लाख करोड़ रुपये डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचे हैं। रिकॉर्ड एमएसपी भी बढ़ाया और पहले की तुलना में बीते दशक में तीन गुना अधिक खरीदी की गई है। किसान को आसान-सस्ता ऋण मिले, उसमें भी तीन गुना वृद्धि की गई है। पहले प्राकृतिक आपदा में किसान को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता था। एक दशक में पीएम फसल बीमा के तहत 2 लाख करोड़ रुपये किसानों को मिले हैं।

एक महत्वपूर्ण निर्णय शिक्षा नीति में बदलाव को लेकर हुआ है। मातृभाषा में पढ़ाई और परीक्षा पर बल दिया गया है। आदिवासी युवाओं के लिए एकलव्य मॉडल स्कूलों का विस्तार हुआ है। 10 साल पहले करीब डेढ़ सौ एकलव्य विद्यालय थे। आज 470 हो गए हैं। अब और 200 से ज्यादा एकलव्य स्कूल की दिशा में केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है।

एसडीजी इंडेक्स के जरिए लगातार मॉनिटरिंग

भारत के सतत विकास के लक्ष्यों की लगातार मॉनिटरिंग की दिशा में नीति आयोग ने 2018 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स की शुरुआत की। यह 113 संकेतकों का उपयोग करके राष्ट्रीय प्रगति को मापता है। इसके माध्यम से सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों के साथ देश के सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के इसमें योगदान और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। इसके जरिए राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की 17 लक्ष्यों पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना की जाती है। स्कोर के आधार पर चार श्रेणियों में इन्हें वर्गीकृत भी किया गया है एस्पिरेंट यानी आकांक्षी (0-49), परफॉर्मर (50-64), फ्रंट-रनर (65-99) और अचीवर (100)। इसके साथ राज्यों के प्रदर्शन पर आधारित एसडीजी इंडिया इंडेक्स नाम से एक डैशबोर्ड भी बनाया गया।

लक्ष्य 1 गरीबी उन्मूलन

गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति

गरीबी को उसके सभी रूपों में मिटाना मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यह भारत के साथ पूरी दुनिया में एक बड़ी चुनौती के रूप में रही है। यह केंद्र सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि बीते 10 साल में 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ सके...

गरीबी में रह रहे लोगों का अनुपात

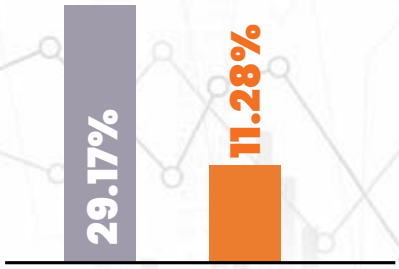

95.40% परिवार पक्के और अर्ध-पक्के घरों में रहते हैं।

99.74%

रोजगार की मांग करने वालों को 2023-24 में मनरेगा के तहत रोजगार की पेशकश की गई। 25 करोड़ से ऊपर हो गई नवंबर, 2024 तक मनरेगा में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या।

- 54.58 करोड़ खाते 15 जनवरी, 2025 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना में खोले गए। करीब 56% खाते महिला के हैं। इन खातों में 2.46 लाख करोड़ रुपये जमा हैं।
- 10.05 करोड़ महिला परिवार को अब तक स्वयं सहायता समूह से दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में जोड़ा गया।
- 22.52 करोड़ व्यक्तियों को नामांकित किया गया है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में, इसमें 8.8 लाख दावों के लिए 17,600 करोड़ रुपये दिए गए।
- 49.12 करोड़ लोगों को कवर किया गया है अभी तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, दुर्घटना दावों के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

- 4.53 करोड़ मकानों को 2 फरवरी, 2025 तक पीएम आवास योजना में मिली है मंजूरी। 3.56 करोड़ मकान का निर्माण हो चुका है पूरा।
- 99 लाख के लगभग ग्रामीण युवा एवं किसान को कौशल विकास योजना के तहत 2021-22 से 2023-24 तक किया गया है प्रशिक्षित।
- 3.09 करोड़ लाभार्थियों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत दी जा रही है वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन।
- 7.33 करोड़ तक पहुंच गई है जनवरी, 2025 तक अटल पेंशन योजना में नामांकन संख्या।

सफलता की कहानी...

जनधन खाते के साथ जीवन ज्योति ने संभाला लीलाबाई का परिवार

छत्तीसगढ़ में जशपुर के करीमीटिकरा की लीलाबाई पोर्ते उन लोगों में से एक हैं, जिनके आड़े वक्त में जनधन खाते और उसके जरिए मिले जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभ ने परिवार को सहारा दिया। बात 2015 की है, पति अभिराम के साथ लीलाबाई के परिवार में दो बेटे व दो बेटियां थी। परिवार खेती और मजदूरी कर जीवन यापन कर रहा था। गांव से बैंक की शाखा 7 किमी दूर होने की वजह से किसी का कोई बैंक खाता नहीं था। एक दिन एक बैंक मित्र गांव पहुंचे और खाते का फायदा बताया। लीलाबाई कहती हैं, एक छोटी सी मशीन से अगूंठे की छाप और पहचान पत्र लेकर उन्होंने हमारा बैंक खाता खोल दिया। मेरे पति ने उस खाते के जरिए जीवन ज्योति योजना का फार्म भी भर दिया। मुझे तब यह नहीं पता था। जून, 2015 में लू की वजह से पति की मृत्यु हो गई। परिवार पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बैंक मित्र को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने हमें पति के बीमा के बारे में बताया और आवश्यक दस्तावेज के बाद दो लाख रुपये मेरे खाते में जमा करा दिए गए।

लक्ष्य 2 कोई भूखा न रहे

जलवायु परिवर्तन और सूखे समेत ऐसे कई कारण हैं, जिनके चलते वर्षों तक आबादी का एक बड़ा हिस्सा भुखमरी व कुपोषण से जूझता रहा। इसीलिए सतत विकास के लक्ष्यों में भुखमरी और कुपोषण की समाप्ति पर दिया खास जोर...

99.01%
लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किए गए।

18.70%
महिलाओं का बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है, 15-49 आयु वर्ग में।

32.10%
पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे कम वजन के हैं, (लक्ष्य 13.3%)

35.50%
पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे बौने हैं (लक्ष्य 23.7%)

- 3,295 परियोजनाओं को राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत दी गई है फरवरी, 2025 तक मंजूरी। 2,381 करोड़ रुपये है परियोजना की लागत, योजना में करीब 1,100 करोड़ रुपये की सब्सिडी भी दी गई है।
- 24.77 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड परीक्षण के बाद प्रधानमंत्री- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के घटक के रूप में 11 फरवरी 2025 तक किसानों को जारी। 8,272 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं देश भर में स्थापित।
- 8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड बनाए, 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई इनकी लोन सीमा। गत 10 वर्ष में किसान क्रेडिट कार्ड के लोन पर 1.44 लाख करोड़ रुपये से अधिक की ब्याज सब्सिडी दी गई।

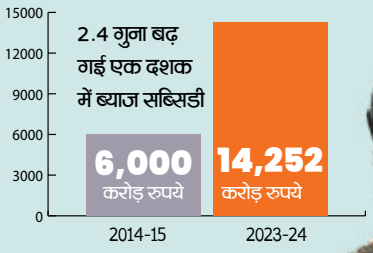

3,052.25
किग्रा प्रति हेक्टेयर है चावल और गेहूं का 3 वर्षीय औसत उत्पादन

- 10.13 करोड़ के लगभग है पोषण अभियान के तहत दिसंबर, 2024 तक लाभार्थी। उद्देश्य 0-6 साल के बच्चे, किशोरी, गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार लाना।
- 1,30,794 करोड़ रुपये राष्ट्रीय पीएम पोषण अभियान पर 2021-22 से 2025-26 तक किए जाने हैं खर्च।
- 99.8% राशन कार्ड आधार कार्ड से जोड़े जा चुके। 99.6% उचित दर दुकान पर ईपीओएस डिवाइस लगे हैं जिससे पारदर्शी हुई राशन वितरण की व्यवस्था। 31 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में राशन आपूर्ति श्रृंखला हुई कंप्यूटरीकृत।
- 63.19 करोड़ किसान के 42.21 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र की फसल का बीमा 2023-24 तक फसल बीमा योजना में किया गया। किसान को 1,75,276 करोड़ रुपये के दावे का भुगतान 32,475 करोड़ रु. भरा।
- 33.17 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में शुरुआत से फरवरी, 2025 तक लाभांवित हुए। 1,646 योजनाओं को दी गई है मंजूरी।
- 13.4 लाख किसान जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार के प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और जलवायु लचीली कृषि क्षमता निर्माण कार्यक्रमों से देश के 151 जलवायु संवेदनशील जिलों में लाभांवित हुए हैं।
- 17 लाख से अधिक पौधे रोपे गए मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव 2024 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत। 2030-31 तक के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- तिलहन को भी मंजूरी।

80.67
करोड़ व्यक्ति को गरीब कल्याण अन्न योजना में दिया जा रहा है नि:शुल्क अनाज

ई-नाम ने तेलंगाना के मुस्कु विद्यासागर की बदली तकदीर

तेलंगाना में बालकोंडा मंडल के वेलकटूर गांव के मुस्कु विद्यासागर के पास 7 एकड़ जमीन है। खेती और कृषि उत्पादों की मार्केटिंग में 20 साल का अनुभव रखने वाले मुस्कु विद्यासागर का नाम उन लोगों में शामिल है, जिन्होंने ई-नाम के जरिये अपने कारोबार को एक नई पहचान दी है। विद्यासागर ने ईएनएएम (प्रत्यक्ष खरीद केंद्र) में 26.16 क्विंटल सफेद सोया बेचा, जिससे उन्हें अतिरिक्त कमीशन के रूप में 1,427 रुपये और एक अन्य तरह के कम शुल्क के रूप में 1,501 रुपये की बचत हुई। 26.16 क्विंटल उत्पाद पर उन्हें करीब 70,000 रुपये की उपज के एक ही सौदे में 2,929 रुपये की राशि का लाभ हुआ। इस प्रकार, 270 क्विंटल सोया बेचकर विद्यासागर ने 2016 में अपनी कृषि उपज पर 30,000 रुपये से अधिक का मुनाफा कमाया, जो पहले कमीशन एजेंटों के पास जाते थे। इसके अलावा, उन्हें ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से बिक्री के 24 घंटे के भीतर उपज का भुगतान प्राप्त हुआ।

सफलता की कहानी...

लक्ष्य 3 स्वास्थ्य व खुशहाली

जीर्ण और भयावह बीमारियां उन मुख्य कारकों में से एक हैं, जो परिवारों को गरीबी और वंचितता की ओर धकेलती हैं। इसीलिए सतत विकास लक्ष्यों में तीसरे स्थान पर स्वस्थ्य और खुशहाल जीवन को महत्व दिया गया है। भारत का स्कोर इस क्षेत्र में 2018 में जहां 52 था, वहीं 2023-24 में यह 77 हो गया है। जानिए कैसे इस दिशा में सफल रहे भारत के प्रयास...

5 वर्ष से कम आयु के शिशु मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर) 2016-18 के 36 से घटकर 2018-20 में 32 पर आया।

97
मातृ मृत्यु दर प्रति 1,00,000 जीवित जन्म पर।

93.23%
बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है 9-11 महीने की आयु वर्ग में।

- स्वास्थ्य संस्थानों में कुल प्रसव 97.18% तक पहुंची।
- 3.69 करोड़ लाभार्थियों को 16,418.12 करोड़ रुपये दिए गए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दिसंबर 2024 तक।
- पांच वर्ष से कम उम्र के शिशु में प्रति हजार जन्म पर 32 मौत।
- 0.05 एचआईवी मरीज प्रति हजार अप्रभावित जनसंख्या में।
- 70 वर्ष पहुंची जीवन प्रत्याशा।
- 12 मौत सड़क हादसे में प्रति एक लाख की आबादी पर।
- 49 स्वास्थ्यकर्मी प्रति एक लाख की आबादी पर।
- 1,75,338 आयुष्मान आरोग्य मंदिर नवंबर 2024 तक चालू हो चुके हैं।

- 12.37 करोड़ परिवार के 55 करोड़ लोग को आयुष्मान भारत के जरिए पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज।
- 17.7% की गिरावट आई 2015 के मुकाबले 2023 में प्रति लाख आबादी टीबी मरीजों में।
- 46.4 लाख किशोरियों को वित्त वर्ष 2024-25 में नवंबर महीने तक सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराया गया।
- 220 करोड़ कोविड वैक्सीन खुराक दी गईं।
- 13,822 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं सितंबर, 2024 तक। 25,000 और केंद्र खोलने की शुरुआत हुई।

- वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य। 2025-26 तक 0-40 आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य।
- 32.6 करोड़ से ज्यादा मरीजों को ई-संजीवनी से चिकित्सीय परामर्श मिला।
- देशभर में बच्चे, किशोरी, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए मिशन पोषण की शुरुआत... 10.02 करोड़ से अधिक लोग ले चुके हैं 2024 तक लाभ।

सफलता की कहानी...

आयुष्मान भारत ने दी जैनब को नई जिंदगी

बात कोविड के दौर की है, जब पूरा देश इस भयानक वायरस के साये में थम चुका था। लोग घरों में कैद थे। मध्य प्रदेश के विदिशा में फिरोज और उनका पूरा परिवार भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताई गई गाइडलाइन के मुताबिक पूरी सावधानी बरत रहे थे। इसके बावजूद उनका पूरा परिवार एक दिन कोविड की चपेट में आ गया। सबसे ज्यादा तकलीफ में उनकी 6 साल की मासूम बेटी जैनब थी। जैनब को कोविड अस्पताल में दाखिल कराया गया। आयुष्मान कार्ड की वजह से उन्हें एक रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा। कुछ दिनों बाद जैनब फिर उसी मुस्कान के साथ घर लौट आई।

लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

96.5%
है प्रारंभिक शिक्षा के लिए समायोजित शुद्ध प्रवेश दर। 2018-19 में यह 87.26% थी। 14 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश 100% हासिल कर चुके हैं।

शिक्षा ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभाने में मदद करती है तो व्यक्तित्व, चरित्र और आदर्शों का भी निर्माण करती है। यही कारण है कि सतत विकास लक्ष्यों में इसे चौथे नंबर पर रखा गया है।

- 98.33% मिडिल स्कूल में पानी 91.77% में बिजली उपलब्ध है।
- 13% रह गई है माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर 2021-22 में। 21% थी 2013-14 में।
- 13.8% की बढ़ोतरी हुई है उच्च शिक्षा संस्थानों में 2022-23 तक 2014-15 के मुकाबले।

100%
सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत।

28.4%
है सकल नामांकन अनुपात 2021-22 तक उच्च शिक्षा में 18-23 आयु वर्ग के लिए।

18 छात्रों पर एक शिक्षक का अनुपात।

76.70% पहुंची साक्षरता दर 15 वर्ष या इससे ऊपर आयुवर्ग के लोगों की।

- सरकार ने 2021-22 से 2025-26 तक सरकारी स्कूलों में भोजन उपलब्ध कराने के लिए 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)' को मंजूरी दी।
- 18,72,000 से अधिक अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 437 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति में जारी की गई।
- 41,32,000 से अधिक अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 4965 करोड़ रुपये से ज्यादा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत राशि प्राप्त हुई।

11,920
पीएमश्री स्कूल खोले गए हैं अब तक। 14,500 खोलने का लक्ष्य।

718 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय अब तक स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 476 शुरू हो चुके हैं, जिनमें 1,36,330 छात्र पढ़ रहे हैं।

स्कॉलरशिप से पूरा हुआ तरम और दीपक का सपना

अरुणाचल प्रदेश के तरम नीलिंग उन छात्रों में से एक हैं, जिनका इंजीनियर बनने का सपना पीएम विशेष छात्रवृत्ति योजना के जरिए पूरा हुआ है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बीटेक करने वाले तरम कहते हैं, स्कॉलरशिप की पहली किस्त में मिली करीब 73,000 रु. की राशि से परिवार तो आर्थिक बोझ से बचा ही, मुश्किल वक्त में किताबों से लेकर दूसरी जरूरतें भी पूरी हुईं। उधर, गुजरात में सूरत के दीपक शंकर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दृष्टिबाधित दीपक 12वीं में अच्छे नंबर लाने के बाद इंजीनियर बनना चाहते थे। उनके बड़े सपनों के सामने आर्थिक स्थिति बाधा बनकर खड़ी थी। यह हकीकत में बदला पीएम छात्रवृत्ति योजना से। इसमें फीस, मेंटनेंस और किताबों के लिए मिली 3.10 लाख रु. की मदद ने मुश्किल वक्त में आर्थिक मदद दी।

सफलता की कहानी...

लक्ष्य 5 लैंगिक समानता

लैंगिक असमानता पूरी दुनिया के लिए लंबे समय तक चुनौती बना रहा है। सतत विकास के पांचवें लक्ष्य के तहत महिला अधिकारों को महत्वपूर्ण माना गया है। भारत उन देशों में शामिल है, जहां मजबूत प्रतिबद्धता के साथ विकास के केंद्र में महिला शक्ति के योगदान को सबसे अहम स्थान दिया जा रहा है...

930
हुआ जन्म के समय लिंगानुपात 2023-24 में। 2014-15 में यह 918 था।

79.4%
है माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं की नामांकन दर।

74.1%
विवाहित महिलाएं परिवार नियोजन की पक्षधर हैं।

0.76
हो गया महिला-पुरुष आय (नियमित वेतनभोगी कर्मचारी) का अनुपात।

- 13.96% हैं महिला ऑपरेशनल लैंडहोल्डर्स।
- 53.90% है 15 से 59 वर्ष आयुवर्ग की किशोरी व महिलाओं के पास मोबाइल फोन।
- 88.70% विवाहित महिलाएं कम से कम तीन घरेलू निर्णयों में भाग लेती हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार।
- 51.67 करोड़ कुल स्वीकृत लोन संख्या मुद्रा योजना के तहत। 34.96 करोड़ महिला लाभार्थी यानी 70% लाभार्थी महिलाएं।
- 4.1 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं नवंबर 2024 तक। 2.64 लाख करोड़ रुपये इन खातों में जमा कराए गए हैं।

404
कार्यशील शक्ति सदन गृहों से 11,196 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।

758
जिलों में 802 वन स्टॉप सेंटर काम कर रहे हैं। 31 दिसंबर, 2024 तक 10.43 लाख महिलाओं को इसमें सहायता मिली।

- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, तकनीकी शिक्षा में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को 10,000 छात्रवृत्ति (प्रगति) प्रदान कर रही है।
- महिला हेल्पलाइन (181-डब्ल्यूएचएल) ने संकट में लाखों महिलाओं की सहायता की है।

- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) और छात्रावासों में लैब एवं स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध कराने का निर्णय। लगभग 290 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस पहल से 7 लाख बालिकाएं होंगी लाभान्वित।

सफलता की कहानी...

बेटी के सुकन्या खाते ने दूर की हुस्ना की चिंता

बिहार के मोतिहारी की हुस्ना को अक्सर अपनी बेटी के भविष्य की चिंता परेशान करती थी। हुस्ना को एक दिन टेलीविजन के जरिए सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पता चला। उन्होंने फौरन योजना के तहत नजदीकी स्टेट बैंक शाखा में जाकर खाता खुलवा लिया। तमाम आर्थिक संकटों के बीच गुजर-बसर करने वालीं हुस्ना तब से हर माह बेटी के खाते में एक हजार रुपये डालना नहीं भूलतीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए हुस्ना कहती हैं, इस योजना ने उनकी बेटी के भविष्य के लिए नींव तैयार करने में मदद की है।

लक्ष्य 6 स्वच्छ जल-स्वच्छता

साफ पेयजल और स्वच्छता जीवन की सबसे बुनियादी जरूरतों में से एक है। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों के जरिए भारत ने इस बुनियादी जरूरत को पूरा करने में सबसे ठोस पहल की है।

94.70%
स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था।

99.29%
ग्रामीण परिवार की स्वच्छ जल के स्रोत तक हुई पहुंच।

- 100% ग्रामीण घर में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण में शौचालयों का निर्माण।
- 100% जिले खुले में शौच से मुक्त हुए सत्यापित।

80%
से अधिक ग्रामीण परिवार के घर में नल से जल आपूर्ति, जो 2019 में महज 16.8 फीसदी घर में थी। 11 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में 100% ग्रामीण घरों में नल से जल।

करीब 5 गुना हुई ग्रामीण परिवारों में नल से जलापूर्ति

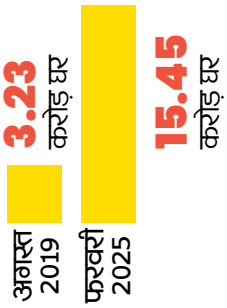

- 1.24 लाख किमी जल नेटवर्क और 35,332 किमी सीवर नेटवर्क को अमृत 2.0 में मंजूरी।
- 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई सुविधा से गत 10 वर्ष में जोड़ा गया है।
- 68,000 से अधिक अमृत सरोवर का निर्माण, जनवरी, 2025 तक।
- 1.66 करोड़ से अधिक जल संबंधित कार्य 31 जनवरी, 2025 तक।
- 705 जल शक्ति केंद्र बनाए।
- 139 करोड़ पौधे गत 5 वर्ष में लगाए।
- 467 परियोजनाएं नमामि गंगे मिशन में अभी तक स्वीकृत।
- 59.26% कुल उपलब्ध भूजल 2021-22 में निकाला गया।

बिहार में जनभागीदारी से जगी स्वच्छता की अलख

बिहार में जनभागीदारी और सामुदायिक जागरूकता ने स्वच्छता की कहानी लिखी। यहां स्वच्छता कवरेज बढ़ाने के लिए तीन महीने के एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अभियान के तहत अप्रैल से जून 2023 तक हर माह की 15 से 24 तारीख के 10 दिन स्वच्छता को समर्पित किए गए। इसके तहत जीविका दीदी, सफाईकर्मी, स्वच्छाग्रही और अन्य स्वयंसेवकों ने मिलकर स्वच्छता से समृद्धि अभियान चलाया। इसके जरिये श्रमदान के स्वच्छता गतिविधियों के लिए समुदायों को शिक्षित करने, उन्हें अभियान से जोड़ने और स्वच्छता के लिए प्रेरित करने का काम किया गया। इस दौरान सार्वजनिक स्थान, सड़क, कचरा स्थल, गंगा नदी के तट, पर्यटक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की सफाई के लिए व्यापक जनभागीदारी ने गति पकड़ी और नतीजा आज बिहार स्वच्छता कवरेज के मामले में शीर्ष राज्यों में शामिल है।

सफलता की कहानी...

लक्ष्य 7 सस्ती, विश्वसनीय स्वच्छ ऊर्जा

सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का मतलब ऐसी ऊर्जा सेवाओं से है, जो आसानी से उपलब्ध हो, सस्ती हो, विश्वसनीय हो और पर्यावरण के लिए टिकाऊ हों। सौभाग्य, उजाला, पीएम सूर्य घर जैसी योजनाओं के साथ मजबूत इरादों के जरिए भारत बढ़ा रहा है इस दिशा में अहम कदम...

100%
घरों तक पहुंची बिजली।

96.35%
घरों में खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन (एलपीजी व पीएनजी) कनेक्शन

- 2.86 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के घरों का अक्टूबर, 2017 में शुरू प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) में विद्युतीकरण किया गया।
- 10.33 करोड़ से अधिक को मिला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में एलपीजी कनेक्शन। इसमें 3.13 करोड़ लाभार्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं।
- 36.87 करोड़ एलईडी बल्ब उजाला योजना में वितरित, जिससे सालाना 19,153 करोड़ रुपये की हुई बचत। यह दुनिया का सबसे बड़ा शून्य-सब्सिडी वाला घरेलू प्रकाश कार्यक्रम बन गया है।

6 लाख
स्टैंड अलोन ऑफ ग्रिड सौर पम्प पीएम कुसुम योजना में लगे, 14 लाख का लक्ष्य है।

- 9,136 सर्किट किमी ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ीं हैं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ने। इससे बिजली आपूर्ति में सुधार हुआ (शहरी क्षेत्र : 23.4 घंटे/दिन, ग्रामीण क्षेत्र : 21.9 घंटे/दिन)।
- 1 लाख करोड़ रुपये के जीवाश्म ईंधन आयात में कमी आने की उम्मीद राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से की गई है। लक्षित मात्रा में उत्पादन-उपयोग से सालाना 50 एमएमटी CO_2 उत्सर्जन में कमी की उम्मीद।
- 16.14 इलेक्ट्रिक वाहन खरीददारों को फेम इंडिया योजना के चरण-दो में सहायता दी गई। पहले चरण में 2.55 लाख वाहनों को सब्सिडी दी गई। इस योजना में 11 हजार से अधिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने हैं।
- 28 लाख से अधिक वाहनों को पीएम ई-ड्राइव दो वर्षीय योजना में सब्सिडी दी जानी है ताकि जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता और कार्बन उत्सर्जन में कमी आए। योजना सितंबर, 2024 में शुरू की गई जिस पर 10,900 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

1.71 करोड़ पंजीकरण
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कराए गए। करीब 8.9 लाख आवासीय घर योजना में रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करके लाभांवित हुए। प्रत्येक जिले में एक मॉडल सौर गांव होगा विकसित।

10 हजार मेगावाट
के अक्षय ऊर्जा विद्युत संयंत्र लगाने का लक्ष्य लेकर बढ़े किसान, 35 लाख ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंप सौरीकरण का काम भी जारी।

उज्ज्वला से मिली रामवती के परिवार को धुएं से मुक्ति

सफलता की कहानी...

उत्तर प्रदेश के बरेली की रामवती के घर में पहले चूल्हे पर खाना पकता था। उस समय को याद कर रामवती कहती हैं, चूल्हे की लकड़ियां इकट्ठी करने दूर तक जाना पड़ता था। कभी लकड़ी नहीं मिली तो ऐसा दिन भी बीता, जब बच्चों को भूखा ही सोना पड़ा। लकड़ियां मिलीं तो आंखों में धुआं और काली दीवारों के साथ बीमारी की चिंता अलग। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए मिले गैस कनेक्शन के बाद रामवती की यह चिंताएं दूर हो गई हैं। बरेली की ही गीता की कहानी भी रामवती की तरह है। गीता कहती हैं, अब न तो उन्हें गीली लकड़ियों की चिंता है और न आंखों में धुएं की।

लक्ष्य 8 सम्मानजनक काम और आर्थिक विकास

समावेशी और सतत आर्थिक विकास किसी भी देश की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण आयाम होता है। जीवन स्तर में सुधार के साथ हर हाथ को काम जरूरी है। भारत में पीएलआई जैसी योजनाओं ने जहां आर्थिक विकास को नई गति दी है तो वहीं बेरोजगारी दर में आई कमी इस लक्ष्य की दिशा में उसकी अहम प्रतिबद्धता को भी दिखाता है।

3.40%
बेरोजगारी दर वर्ष 2022-23 में जबकि वर्ष 2018-19 में यह दर 6.2% थी।

5.88%
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर 2022-2023 में।

- 56% प्रधानमंत्री जनधन खाते महिलाओं ने खुलवाए हैं।
- 95.70% घरों में एक सदस्य का बैंक या डाकघर में खाता है।

18
एटीएम हैं और 12 बैंकिंग आउटलेट प्रति 1 लाख आबादी पर।

कौशल विकास के जरिए नेहा के परिवार को मिली मुस्कान

राजस्थान के कुशलपुरा की नेहा पेठारी आज अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ बनी हुई हैं। हालांकि, कुछ समय पहले ऐसा नहीं था। आर्थिक संकट से जूझ रहे उनके परिवार के आगे जरूरत की चीजें भी जुटाना मुश्किल था। ऐसे में नेहा ने प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र जॉइन किया। यहां से सिलाई की ट्रेनिंग करने के बाद नेहा अब गांव में खुद की दुकान चलाती हैं। कौशल विकास केंद्र ने नेहा में न सिर्फ आत्मनिर्भरता का नया विश्वास पैदा किया, बल्कि कुछ करने का हौसला भी जगाया। नेहा कहती हैं, कभी यह सोच भी नहीं सकती थी कि पूरा परिवार मैं अकेली चला सकती हूं, लेकिन आज मजबूत इरादे के साथ अपना काम और आगे बढ़ाना चाहती हूं।

सफलता की कहानी...

- 1.46 लाख करोड़ रुपये का निवेश अगस्त 2024 तक पीएलआई के 14 क्षेत्रों में आया है। 12.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन। 9.5 लाख रोजगार सृजन और 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात हुआ।
- 13,554 करोड़ रु. वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक खर्च को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए मंजूरी दी गई है।
- 2.27 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं कौशल भारत कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे पीएमकेवीवाई, पीएम-एनएपीएस और जन शिक्षण संस्थान योजना में।
- कौशल भारत कार्यक्रम को फरवरी, 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी है।
- 1.61 करोड़ उम्मीदवार को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 तक दिया गया प्रशिक्षण। इसमें करीब 45% महिलाएं। प्रमाणित करीब 43% उम्मीदवारों को मिला प्लेसमेंट।
- 32.61 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि के 51.67 करोड़ से अधिक लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अप्रैल, 2015 से 2 फरवरी, 2025 तक स्वीकृत किए गए।
- 27.73 लाख प्रशिक्षुओं को नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में मौके मिले तो वहीं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना में 8.80 लाख प्रशिक्षुओं को अवसर मिले।
- 10.05 करोड़ महिला परिवार को 90.90 लाख एसएचजी से जोड़ा, इन समूह को 20 लाख रुपये तक लोन दिया जाता है। 9.74 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन दिया गया।
- 71.65 लाख स्ट्रीट वेंडर की पहचान की गई राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में, करीब 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए गए, 15.45 लाख युवाओं का कौशल विकास और 17 लाख से अधिक बैंक लोन दिए गए।
- 4.63 करोड़ से अधिक **MSME** उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत हैं।
- 61.60% श्रम बल भागीदारी दर।

99.70%

लक्षित बस्तियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सभी मौसम के अनुकूल सड़क नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है।

लक्ष्य 9 उद्योग, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर

औद्योगिक विकास किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी नींव और इनोवेशन भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में सबसे अहम कदम है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ भारत ने इस क्षेत्र में तेज की है अपनी प्रगति की रफ्तार...

- 14.34% हिस्सेदारी सकल मूल्य संवर्धन में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की है।
- 11.42% वर्क फोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कार्यरत।
- 54.18% हिस्सेदारी कुल सकल मूल्य संवर्धन में सेवा क्षेत्र की है।
- 46वां रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का विश्व के 132 देशों में।
- 93.30% घरों में कम से कम एक मोबाइल फोन है।
- 95.08% गांवों में 3जी या 4जी मोबाइल इंटरनेट कवरेज है।

डिजिटल इंडिया

141 करोड़

लोगों के आधार नंबर बनाए जा चुके हैं अब तक। मार्च, 2014 तक 61.01 करोड़ बने थे।

11 करोड़

किसानों का आईडी पूर्वोत्तर के सभी किसान की डिजिटल पहचान सहित बनाने का लक्ष्य वर्ष 2026-27 तक रखा गया है। 2 करोड़ से अधिक आईडी बनाए जा चुके हैं।

- 2.51 लाख से अधिक ग्राम पंचायत ई-ग्राम स्वराज में ऑनबोर्ड हुई हैं।
- 23.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन यूपीआई के माध्यम से दिसंबर, 2024 में किया गया, दिसंबर, 2016 में महज 707.93 करोड़ रुपये का लेनदेन यूपीआई से किया गया था।
- 49% वैश्विक डिजिटल वास्तविक समय भुगतान भारत में हो रहा है, एसीआई वर्ल्डवाइड रिपोर्ट 2024 के अनुसार।

डिजिटल लेनदेन

44% रही 2017-18 से 2023-24 तक डिजिटल लेनदेन में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर

- 46.52 करोड़ हो गए हैं 1 फरवरी, 2025 में डिजीलॉकर के उपयोगकर्ता, यह डिजिटल दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रमुख प्लेटफॉर्म है।
- 556.37 करोड़ शिक्षण सत्रों का आयोजन दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल शिक्षा मंच दीक्षा पर जुलाई 2024 तक किया गया।

पीएम गति शक्ति

- 15.89 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 228 बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का मूल्यांकन पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में किया गया।
- 75,000 करोड़ रुपये रेल व सड़क परिवहन के 100 से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए 2023-24 में बजट में रखे गए।
- 27 आकांक्षी जिलों में प्रयोग के तौर पर जिला मास्टर प्लान बनाने की शुरुआत अक्टूबर, 2024 में पीएम गति शक्ति जिला मास्टर प्लान पोर्टल से की गई है।

औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम

- राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 11 औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं।
- 28,602 करोड़ रुपये की लागत वाली 12 नई औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना की मंजूरी मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज के विकास के लिए दी गई है।

भारतमाला परियोजना

26,425 किलोमीटर लंबाई को कवर करने वाली 8.54 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं भारतमाला परियोजना में सौंपी जा चुकी हैं जिसमें 19,201 किलोमीटर का निर्माण पहले ही पूरा किया जा चुका है।

पीएम मित्र पार्क

7 पीएम मित्र पार्क 2027-28 तक स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। तमिलनाडु के विरुद्धनगर, तेलंगाना के वारंगल, गुजरात के नवसारी, कर्नाटक के कलबुर्गी, मध्य प्रदेश के धार, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और महाराष्ट्र के अमरावती में इसके लिए जगह की पहचान की जा चुकी है।

मेक इन इंडिया और स्टार्टअप

- 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं केंद्र सरकार मेक इन इंडिया 2.0 में, भारत को मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से 2014 में मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की गई।
- 1,57,706 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई 55 से अधिक उद्योगों में दिसंबर, 2024 तक। इन कंपनियों ने 17.2 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए। 118 कंपनियां यूनिकॉर्न बनी हैं।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति (एनएलपी 2022)

- 2030 तक भारत की लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में सुधार कर इसे 25 शीर्ष देश में शामिल करना राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।
- पीएम गतिशक्ति एनएमपी के पूरक के रूप में 17 सितंबर, 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की शुरुआत की गई।

22वीं

रैंकिंग है लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इंडेक्स 2023 के अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत की। कुल स्कोर के हिसाब से 38वीं रैंकिंग है।

सफलता की कहानी...

आकिब के लिए डिजिटल इंडिया ने खोली रोजगार की राह

वाराणसी के आकिब की आंखों में पढ़ाई पूरी करने के बाद सपने तो बहुत थे, लेकिन रोजगार के बिना सब कुछ अधूरा ही था। ऐसे में डिजिटल इंडिया से आकिब को नई राह मिली। एक दोस्त से मिली जानकारी के बाद आकिब ने कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत की। इससे आकिब को तो रोजगार मिला ही, आसपास के लोगों को भी सहूलियत हो गई, क्योंकि तमाम तरह के प्रमाण पत्र से लेकर खाता खुलवाने जैसे दूसरे जिन कामों के लिए उन्हें दूर जाना पड़ता था, वह अब आकिब के सेंटर पर ही होने लगे। यासीन कहते हैं, अब मुझे जिस काम के लिए बड़ी दूर चलकर जाना पड़ता था, वह अब आकिब के सेंटर से ही हो रहा है तो इससे बेहतर मेरे लिए और क्या हो सकता है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

- भारत में व्यापार की सुगमता को बढ़ाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 में कंपनियों की स्वैच्छिक स्ट्राइक ऑफ प्रक्रिया को केंद्रीकृत और तेज बनाने के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग कार्पोरेट एग्जिट (सी-पेस) की स्थापना की गई।
- 25,515 कंपनियों को गत दो वित्त वर्ष में स्ट्रक ऑफ कर दिया गया। ऐसे आवेदन निपटाने का औसत समय अब 70-90 दिन रह गया है।
- 63 अपराधों को कंपनी और एलएलपी अधिनियम के अंतर्गत अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया।
- 54 से अधिक प्रारूपों को स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस में परिवर्तित किया गया जिसके लिए पहले क्षेत्रीय कार्यालयों का अनुमोदन आवश्यक था।
- कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरण के लिए शून्य लागत किया गया।

लक्ष्य 10 असमानता में कमी लाना

आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम

- जनवरी 2018 में देश के 112 सबसे कम विकसित जिलों में प्रभावी तरीके से बदलाव के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 49 प्रमुख संकेतकों पर होती है आकांक्षी जिलों की निगरानी।
- यूएनडीपी की 'आकांक्षी जिला कार्यक्रमःएक मूल्यांकन' रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे बेहतर शासन और प्रतिस्पर्धी संघवाद के माध्यम से त्वरित विकास जैसे विभिन्न पहलुओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
- 7 जनवरी, 2023 को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसमें सबसे कठिन और अपेक्षाकृत अविकसित 500 ब्लॉक को 329 जिलों से शामिल किया गया है।

"सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र और 'सर्व पंथ समभाव', जिसका अर्थ है कि सभी धर्म समान हैं, के सिद्धांतों के साथ लोगों की सेवा करने का प्रयास किया है।"

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम: बदलाव की नई दिशा

4,800

करोड़ रुपये के बजट के साथ उत्तरी सीमा से सटे 5 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के 46 ब्लॉक के चुनिंदा गांव में विकास के लिए 2023 में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई।

- 2,400 करोड़ रुपये सड़क व पुलों के निर्माण के लिए आवंटित किए गए हैं तो 626 इंफ्रास्ट्रक्चर और 901 रोजगार संबंधी परियेजनाएं पहले ही शुरू क जा चुकी हैं।
- 362 गांव में जून 2025 तक 4जी कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाएगी तो 662 गांव में से 474 गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है।

पीएम विश्वकर्मा योजना: हुनर को सम्मान

- 27.25 लाख लाभार्थियों का 10 फरवरी तक किया गया पंजीकरण जो अपने हाथ और औजार से काम करने वाले 18 व्यवसाय के कारीगर और शिल्पकार हैं।
- 5% ब्याज पर पहली किश्त में 18 महीने के पुनर्भुगतान अवधि के साथ 1 लाख रुपये और दूसरी किश्त में 30 महीने की पुनर्भुगतान अवधि के साथ 2 लाख रुपये का लोन दिया जाता है।
- 12.40 लाख से अधिक लाभार्थियों ने नवंबर, 2024 तक प्रशिक्षण पूरा किया, 1.49 लाख लाभार्थियों को 1,190 करोड़ रुपये लोन दिया गया।

अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अंब्रेला कार्यक्रम

- 19.3% है देश में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी, इनके उत्थान के लिए 90 अल्पसंख्यक सघनता वाले जिले, 710 ब्लॉक और 66 कस्बे की पहचान की गई। 15 सूत्री प्रधानमंत्री के नए कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभिन्न मंत्रालय की ऐसी योजनाएं और पहल शामिल हैं जो अल्पसंख्यकों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान दे सकें। 4.68 लाख लाभार्थियों को सीखो और कमाओ योजना में प्रशिक्षित किया जा चुका है जबकि नई मंजिल योजना और उस्ताद योजना में करीब 1.20 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। 14,660 करोड़ रुपये गत पांच वर्ष में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए खर्च किए हैं।

45.61%	**28.57%**	**50.40%**
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सीटें	विधान सभा में एससी/एसटी का प्रतिनिधित्व	पेशेवर और तकनीकी कर्मचारी के रूप में काम करने वाले महिला-पुरुष श्रमिकों का अनुपात

पीएम जनमन

- 18 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 पीवीजीटी समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम जनमन) की शुरुआत।
- 11 लाख पीवीजीटी परिवार को लाभांवित करने के लिए 9 मंत्रालय कर रहे हैं काम।
- 3.36 लाख मकान, 4,485 किलोमीटर संपर्क मार्ग का निर्माण करने के साथ ही 1.50 लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन)

- 6,600 करोड़ रुपये के खर्च वाली पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम डिवाइन) योजना को 2022-23 से 2025-26 तक के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।
- 4927 करोड़ रुपये की 36 परियोजना को 31 जनवरी, 2025 तक दी गई है योजना में मंजूरी। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कनेक्टिविटी और आजीविका से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना पीएमजेवीके

25,196

करोड़ रुपये की 5.97 लाख परियोजना पर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में किया गया है काम।

लक्ष्य 11 स्थाई शहर और समुदाय

शहरी इलाकों के निर्माण और प्रबंधन के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव किए बिना सतत विकास हासिल नहीं किया जा सकता। 11वां लक्ष्य इसी तथ्य पर आधारित है। पीएम आवास योजना से लेकर अमृत, हृदय और स्मार्ट सिटी मिशन तक भारत बढ़ रहा है इसी दिशा में...

78%

से ज्यादा कचरा नगरीय निकायों द्वारा प्रसंस्कृत किया जा रहा है।

95%

से ज्यादा घर शौचालय युक्त हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी के जरिए।

- 100 फीसदी वार्ड में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की शुरुआत हुई।
- 100 स्मार्ट शहरों मे कुल 1,64,514 करोड़ रुपये की कुल 8,058 परियोजनाएं स्वीकृत। इनमें से 1,50,157 करोड़ रुपये की 7,491 परियोजना यानी 93% का कार्य पूरा।

शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए सिटीज 2.0 को 2023 से 2027 तक के लिए मंजूरी।

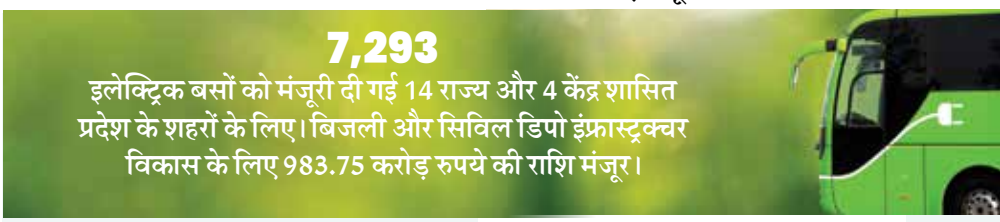

7,293

इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी गई 14 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश के शहरों के लिए। बिजली और सिविल डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 983.75 करोड़ रुपये की राशि मंजूर।

- 4.53 करोड़ मकान को 2 फरवरी, 2025 तक पीएम आवास योजना में मंजूरी, 3.56 करोड़ मकान का निर्माण हो चुका है पूरा।
- पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 68 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को 13,764.55 करोड़ रुपये वितरित।
- अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत 58,66,237 नल से जल कनेक्शन दिए गए। 2,449 पार्क विकसित किए गए। 37,49,467 सीवर कनेक्शन और 62,78,571 एलईडी वाले स्ट्रीट लाइट लगाए गए।
- राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना (हृदय) के तहत 77 परियोजनाओं के लिए 428 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मंजूर।

11

रेलवे स्टेशन के साथ नमो भारत रैपिड रेल का दायरा 55 किलोमीटर तक फैला।

1,000

किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क। मेट्रो अब 13 राज्यों के 23 शहरों तक पहुंची।

लक्ष्य 12 जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन

2020 में अक्षय ऊर्जा से बिजली उत्पादन में सुधार 36.37% से बढ़कर 2024 में 43.28% हुआ। 94.86% उद्योग पर्यावरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

32.45
लाख करोड़ रुपये
के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई गांधीनगर में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो (री-इन्वेस्ट) 2024 के चौथे संस्करण में।

कई संशोधनों के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 को मंजूरी दी। इसमें पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले 2025-26 में ही प्राप्त करने के लिए पहल करना प्रमुख।

2014 में इथेनॉल मिश्रण 1.53% से बढ़कर 2024 में 15 प्रतिशत हुआ।

16,71,606
बेचे गए वाहनों की संख्या फेम इंडिया के तहत। 1,02,517 टन CO2 में कमी।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2021 में घोषित लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) अभियान के अनुरूप, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 26 सितंबर 2024 को इकोमार्क नियमों को अधिसूचित किया। यह वर्ष 1991 की इकोमार्क योजना का स्थान लेगा।
- जनवरी 2025 तक, देश की गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता 217.62 गीगावाट तक पहुंच गई। सीसीडीसी पवन पहल ने पवन ऊर्जा विकास को काफी विस्तार दिया है, जिससे इस क्षेत्र की स्थापित क्षमता 48.16 गीगावाट हो गई है।

54.99%
खतरनाक अपशिष्ट पुनर्चक्रित किया गया उत्पन्न कुल खतरनाक अपशिष्ट का।

166.43
किलोग्राम जीवाश्म ईंधन की खपत प्रति व्यक्ति।

90.52%
उत्पन्न जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का उपचार किया गया।

65.24%
नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग कुल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम (एनपीके) में से किया गया।

1,000
की आबादी पर प्रति वर्ष 3.04 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है।

लक्ष्य 13 जलवायु अनुकूल कार्रवाई

19.20
है भारत का आपदा संबंधित तैयारी सूचकांक। यह आपदाओं के प्रति लोगों की तैयारी के स्तर को मापता है।

हर 10 लाख लोगों पर **15** की मौत मौसम संबंधी आपदाओं की वजह से हुई है।

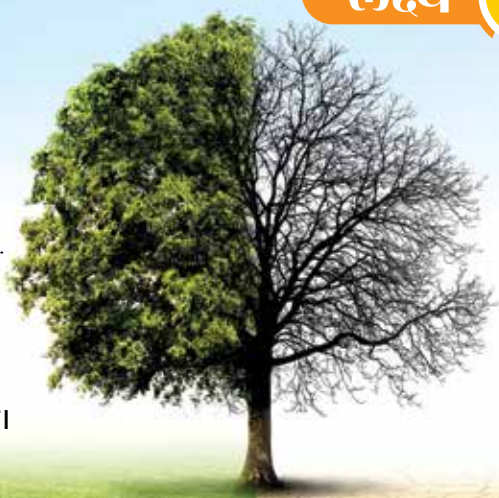

सतत विकास के सामने आज जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा रोड़ा है। औद्योगिकीकरण के साथ पर्यावरण संरक्षण बड़ा सवाल है तो भारत अपनी रीति और नीति के साथ आशा का केंद्र बना हुआ है। बात चाहे पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली की हो या सौर ऊर्जा के साथ विकास की... भारत ने जैव विविधता के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मजबूत कदम उठाए हैं।

43.28%
तक पहुंचा अक्षय ऊर्जा से बिजली उत्पादन। 2020 में यह 36.37% था।

97.86
गीगावाट पहुंची राष्ट्रीय सौर मिशन से ऊर्जा विकास की स्थापित क्षमता।

2016
में यह 9.01 गीगावाट थी।

- 94.86% उद्योग पर्यावरण मानकों का अनुपालन करते हैं।
- पर्यावरण संरक्षण प्रयास और प्रगति के मामले में जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत 7वें नंबर पर है। 2014 में 30वां था।
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में आठ राष्ट्रीय मिशनों की रूपरेखा दी गई है, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास को बढ़ावा देना है।
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) में 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 130 शहरों को शामिल किया गया। इनमें से 97 शहरों में वित्त वर्ष 2023-24 में पीएम10 सघनता के मामले में 2017-18 की तुलना में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
- हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य भारत के वन की सुरक्षा के साथ जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना।

- 181 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल को प्रतिस्थापित करने में मदद मिली इथेनॉल मिश्रण से 2014 और 2024 के बीच।
- 544 लाख मीट्रिक टन की कटौती की कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में अभी तक।
- 1.1 ट्रिलियन रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो चुकी है।

- पीएम-कुसुम और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसान और परिवारों के बीच सौर ऊर्जा अपनाने में तेजी ला रही है।
- 417.98 मेगावाट स्थापित क्षमता हासिल हो चुकी है बंजर, गैर-कृषि योग्य जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र के जरिए।
- 6.69 लाख बिजली से चलने वाले कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों में बदला जा चुका है अब तक।

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए)

तीन प्रमुख घटक

- वर्षा आधारित क्षेत्र विकास।
- खेत पर जल प्रबंधन।
- मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन।

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी) को दो चरणों में 8 तटीय राज्यों में लागू किया गया। चरण-I में आंध्र प्रदेश और ओडिशा तो चरण-II के तहत छह राज्यों गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल।

लक्ष्य 14 जल में जीवन

जल के नीचे जीवन या जलीय जीवन वह क्षेत्र है, जिस तरफ आजादी के बाद बेहद कम ध्यान दिया गया था। अब नीली क्रांति के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए भारत बढ़ रहा है आगे...

वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

20 हजार करोड़ रुपये

से ज्यादा की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कर नीली क्रांति की दिशा में अब तक का सबसे प्रभावी कदम उठाया।

- 25 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश में केन-बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखी गई।
- यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है।
- मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की 65 लाख से अधिक आबादी को इससे सीधा फायदा होगा।

वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव कवर 4,991.68 वर्ग किलोमीटर है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15 प्रतिशत।

देश में आर्द्रभूमि (झीलों सहित) के संरक्षण और प्रबंधन के लिए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना लागू की जा रही है।

3,682 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था आजादी के बाद से इस योजना की शुरुआत तक मत्स्य क्षेत्र में केवल।

सागरमाला कार्यक्रम

5.5 लाख करोड़ के अनुमानित लागत की लगभग 839 परियोजनाओं के कार्यान्वयन की पहचान।

1.41 लाख करोड़ रुपये के निवेश से सागरमाला कार्यक्रम की अब तक 272 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

सफलता की कहानी...

सिरसा के गांव में लोगों का सहारा बनी पीएम मत्स्य संपदा योजना

सिरसा के राजस्थान सीमा से सटे गांव में खारे पानी के बढ़ते जलस्तर से जमीन बंजर होने लगी थी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का सहारा मिला तो वहां के किसानों ने खारे पानी में झींगा मछली का पालन शुरू किया। मछली पालक सुमित्रा कहती हैं कि 2021 में झींगा की खेती शुरू की। चेन्नई से मछली के तीन लाख बच्चे लाए। यूं तो 120 दिन लगते हैं लेकिन 106 दिन के बाद ही 25 लाख रुपये के झींगा बेच दिए, तुरंत खाते में पैसे आ गए। सुमित्रा ने 2022 में ढाई एकड़ की जगह पांच एकड़ में झींगा पालन किया। कहती हैं इसमें नुकसान की आशंका बहुत कम है, इसलिए मछली पालक बढ़ रहे हैं।

लक्ष्य 15 भूमि पर जीवन

जीवन को सुरक्षित करने के साथ जमीन के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना इसका सबसे अहम उद्देश्य है। सतत विकास के 15वें लक्ष्य के अनुरूप मरुस्थलीकरण से निपटने, भूमि क्षरण को रोकने और जैव विविधता को नुकसान से बचाने की दिशा में भारत ने उठाए हैं अहम कदम...

8,27,357
वर्ग किलोमीटर हुआ देश का वन एवं वृक्ष आवरण।

25.17
प्रतिशत है यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का।

7,15,343
वर्ग कि.मी. (21.76%)
वन आवरण

1,12,014
वर्ग कि.मी. (3.41%)
वृक्ष आवरण

भारत विश्व का सबसे बड़ा बाघ रेंज वाला देश।

छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास-तमोर पिंगला 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित।

वैश्विक आबादी का **75%** बाघ भारत में हैं।

- भारत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को दोबारा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध।
- इसमें से 22.50 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि पहले ही विकसित की गई।
- भारत में दुनिया की 8% जैव विविधता। इसमें कई ऐसी प्रजातियां जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती।

715
करोड़ रु. आवंटित, गत 3 वर्ष में बाघ परियोजना के तहत किए गए।

33 हाथी रिजर्व के साथ जंगली एशियाई हाथियों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या भारत में।

अनुमानतः भारत में उनकी संख्या लगभग **30,000**

सफलता की कहानी...

बंजर जमीन को हरे-भरे जंगल में बदलने वालीं 'वृक्षों की मां'

'वृक्षों की मां' के नाम से पहचान रखने वाली पद्मश्री तुलसी गौड़ा ने कर्नाटक में लाखों पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए 60 से ज्यादा साल समर्पित किए। इससे बंजर जमीन हरे-भरे जंगलों में बदल गई। उनके काम ने पर्यावरण संरक्षण में एक स्थायी विरासत छोड़ी। तुलसी गौड़ा ने कभी कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, फिर भी उनके ज्ञान ने उन्हें "वन के विश्वकोश" के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने निस्वार्थ भाव से पृथ्वी की देखभाल और सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।

लक्ष्य 16 शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं

हिंसा और असुरक्षा की भावना जन मानस को तो प्रभावित करती ही है, देश के विकास पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि सतत विकास के 16वें लक्ष्य के रूप में शांति, न्याय और मजबूत संस्थाओं को रखा गया है। 1860 के पुराने कानूनों की बजाय नई भारतीय न्याय संहिता समेत कई महत्वपूर्ण कदम के साथ भारत ने इस दिशा में मजबूती से बढ़ाए कदम...

89.10%

जन्म पंजीकरण हो रहा है 5 साल से कम उम्र के बच्चों का। इसे 100 फीसदी पर लाने का लक्ष्य है।

- 3 मामले प्रति 10 लाख जनसंख्या पर दर्ज किए भ्रष्टाचार के।
- 19 बच्चों की गुमशुदगी के मामले आए प्रति 10 लाख की आबादी पर। सतत विकास लक्ष्य इस आंकड़े को 0 पर लाना है।
- 37 मामले बच्चों से जुड़े संज्ञेय अपराधों के दर्ज किए गए प्रति 1 लाख की आबादी पर।
- 71 फीसदी ज्यादा पहुंची चार्जशीट दाखिल करने की दर। लक्ष्य 100 प्रतिशत मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की।
- 2 न्यायालय हैं प्रति एक लाख लोगों पर। इस दिशा में सतत विकास लक्ष्य 4.25 का है।

पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

154.84

पुलिसकर्मी हैं प्रति एक लाख आबादी पर

- देश के सभी 17,166 पुलिस स्टेशन अपराध, अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम से जुड़े हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं।
- भगोड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए सभी राज्यों की पुलिस को भारतपोल पोर्टल से जोड़ा गया है। 195 देशों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां इससे जुड़ी हुई हैं।

सूचना का अधिकार कानून

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, संसद ने पास किया था। यह कानून अब पूरे देश में लागू है।

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस)

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य देशभर में बाल संरक्षण के लिए समर्पित और गुणवत्तापूर्ण कर्मियों, संरचनाओं और सेवाओं का सुरक्षा जाल स्थापित करना है।

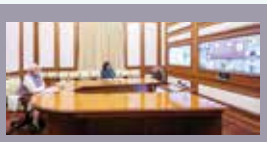

₹19.12 लाख करोड़

की कुल लागत की 363 परियोजनाओं की समीक्षा प्रगति 2.0 प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2024 तक की। लंबित परियोजनाओं की प्रगति को जांचने और समयबद्धता तय करने के उद्देश्य से मार्च, 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

- भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के सहयोग से इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
- 2.54 लाख ग्राम पंचायत ने ई-ग्राम स्वराज डिजिटल प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर 2024-25 में विकास योजनाएं तैयार और अपलोड कीं।
- 2.41 लाख ग्राम पंचायत ने 15वें वित्त आयोग के अनुदान के लिए ऑनलाइन लेनदेन पूरा किया तो पंचायत मिशन मोड परियोजना में 5.15 लाख ऑडिट प्लान और ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई ।

ग्राम न्यायालय सहित न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास

- अक्टूबर 2024 तक देशभर में 313 ग्राम न्यायालय कार्यशील हैं। इनमें दिसंबर, 2020 से अक्टूबर, 2024 तक 2.99 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है। 688 जिला न्यायालय हैं देशभर में।
- समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए तालुका स्तर से लेकर सर्वोच्च न्यायालय स्तर तक विधिक सेवा संस्थान स्थापित किए गए हैं।

लक्ष्य 17 लक्ष्यों के लिए साझेदारी

सतत विकास का महत्वपूर्ण और 17वां लक्ष्य, सभी 16 लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में वैश्विक साझेदारी से जुड़ा हुआ है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस से लेकर लाइफ मूवमेंट तक वैश्विक मंचों पर भारत की कई पहल को दुनिया ने सराहा है...

मिशन लाइफ (पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली)

- **मिशन लाइफ :** वर्ष 2022 में भारत द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक पहल है। यह पहल सभी को अपने जीवन में सरल एवं पर्यावरण अनुकूल कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।
- **इस पहल के सात प्रमुख विषय :** पानी की बचत, ऊर्जा का संरक्षण, कचरे को कम करना, ई-कचरे का प्रबंधन, एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को खत्म करना, यथासंभव खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देना और स्वस्थ जीवनशैली।
- **यूएनईए प्रस्ताव :** संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनईए) ने 1 मार्च 2024 को केन्या के नैरोबी में आयोजित छठे सत्र में सतत जीवन शैली पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित यह प्रस्ताव भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन

- पेरिस में 2015 में आयोजित सीओपी 21 के साथ भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की घोषणा की। यह दुनिया का अकेला ऐसा अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है, जिसका मुख्यालय भारत में है।
- आईएसए का लक्ष्य 2030 तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त करना है।
- साथ ही इसका उद्देश्य 1 बिलियन लोगों तक ऊर्जा की पहुंच प्रदान करना और **1,000** गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है।
- आईएसए वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में काम कर रहा है। इसके साथ ही इससे सालाना 1,000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आएगी। वर्तमान में 120 देश इसके सदस्य हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आईएमईसी की पहल

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 9 सितंबर 2023 को दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं निवेश और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) के लिए साझेदारी पर कार्यक्रम की सह-अध्यक्षता की।
- इसमें भारत को खाड़ी क्षेत्र से जोड़ने वाला एक पूर्वी गलियारा और खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ने वाला एक उत्तरी गलियारा शामिल है। इसमें रेलवे और जहाज-रेल नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे।
- इसका उद्देश्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच निवेश और संपर्क बढ़ाना है।

मेलजोल से समृद्धि का पाठ पढ़ाती है भाषा

भाषा केवल संवाद का माध्यम ही नहीं, यह हमारी सभ्यता-संस्कृति की संवाहक होने के साथ आत्मा भी होती है। भाषाएं समाज में जन्म लेती हैं तो समाज के निर्माण में उतनी ही अहम भूमिका भी निभाती हैं। हाल ही में मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसका इंतजार देश-दुनिया में फैले 12 करोड़ से अधिक मराठी भाषी लोग दशकों से कर रहे थे। भाषाओं को समृद्ध करने की कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी को नई दिल्ली में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन को किया संबोधित...

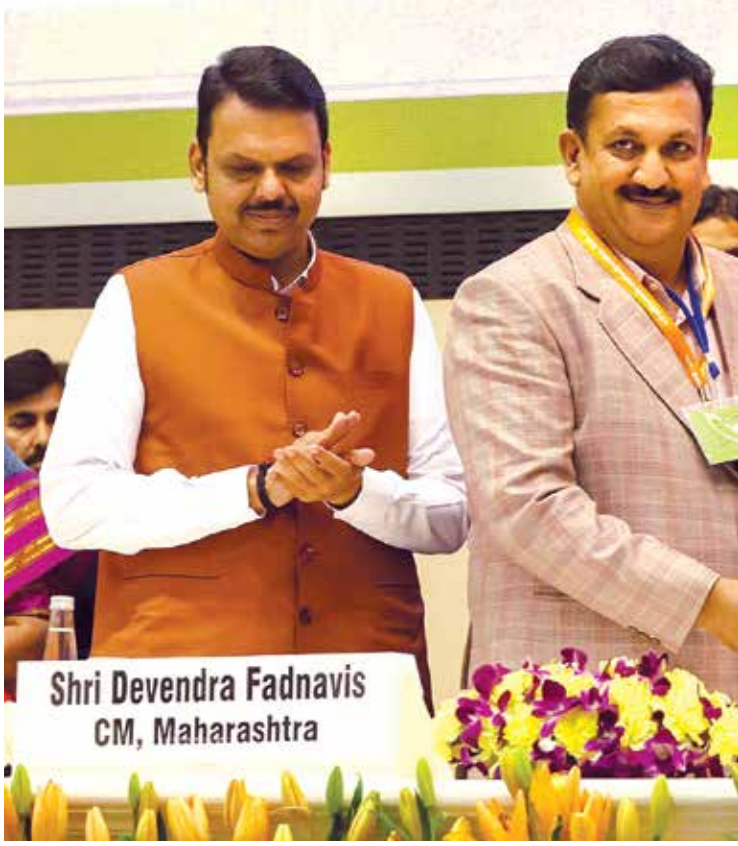

भारतीय भाषाओं में कभी कोई आपसी वैर नहीं रहा, बल्कि उन्होंने सदैव एक-दूसरे को अपनाया और समृद्ध किया है। केंद्र की वर्तमान सरकार ने पहली बार एक साथ मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को गत वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया, जिसके बाद अब शास्त्रीय भाषा की संख्या 11 हो गई है। नई दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन किसी भाषा या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इस सम्मेलन में आजादी की लड़ाई की महक के साथ-साथ महाराष्ट्र और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत भी है।

अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में 21 से 23 फरवरी तक पैनल चर्चा, करीब 50 पुस्तकों का लोकार्पण, 100 बुक स्टॉल पर पुस्तकों की प्रदर्शनी और 2,600 से अधिक कविता का पाठ किए जाने के साथ मराठी साहित्य की कालातीत प्रासंगिकता का कीर्तिगान किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में 71 वर्ष के बाद आयोजित हुए मराठी साहित्य सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुलामी के सैकड़ों वर्ष के लंबे कालखंड में मराठी भाषा आक्रांताओं से मुक्ति का भी जयघोष बनी। वासुदेव बलवंत फड़के, लोकमान्य तिलक और वीर सावरकर जैसे सेनानियों ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। उनके इस

> “मराठी एक संपूर्ण भाषा है। इसीलिए, मराठी में शूरता भी है, वीरता भी है। मराठी में सौंदर्य भी है, संवेदना भी है, समानता भी है, समरसता भी है, इसमें आध्यात्म के स्वर और आधुनिकता की लहर भी है। मराठी में भक्ति-शक्ति और युक्ति भी है।
>
> - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

भाषा विकास और संरक्षण के लिए इन कदमों को जानें...

- शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसी भी भाषा को मिलने पर उस भाषा के लिए सम्मान, प्राचीन भाषाओं में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र व केंद्रीय विश्वविद्यालय में व्यवसायिक पीठों का सृजन शामिल है।
- 10 हजार से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली मातृभाषा या भारतीय भाषा एवं उनकी संस्कृति का दस्तावेजीकरण का काम भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर कर रहा है। पहले चरण में 117 जनजातीय भाषाओं की पहचान की गई है, ताकि उन भाषाओं पर काम किया जा सके।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और भारतीय भाषाओं को जीवंत बनाए रखने के प्रावधान किए गए हैं। कम से कम 5वीं तक और अधिकतम कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा में रखने का प्रावधान किया गया है।

33 भारतीय भाषाओं में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) पोर्टल पर पाठ्य पुस्तक और शिक्षण संस्थान की पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध हैं।

मां की तरह होती है भाषा

भाषा उस मां की तरह होती है, जो अपने बच्चों को नए से नया और अधिक से अधिक ज्ञान देना चाहती है, भेदभाव नहीं करती। भाषा हर विचार का, हर विकास का आलिंगन करती है। मराठी का जन्म संस्कृत से हुआ है, लेकिन इसमें उतना ही प्रभाव प्राकृत भाषा का भी है। पीएम मोदी ने कहा कि कई बार जब भाषा के नाम पर भेद डालने की कोशिश की जाती है तो भाषाओं की साझी विरासत ही उसका सही जवाब देती है। भाषाओं को समृद्ध करना, उन्हें अपनाना, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। इसीलिए आज हम देश की सभी भाषाओं को मुख्यधारा की भाषा के रूप में देख रहे हैं। हम मराठी समेत सभी प्रमुख भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं।

साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक

कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होने के साथ पथ प्रदर्शक भी है। इसीलिए साहित्य सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों की साहित्य से जुड़ी संस्थाओं की देश में अहम भूमिका होती है। 2027 में साहित्य सम्मेलन की इस परंपरा को 150 वर्ष पूरे होंगे। तब 100वां सम्मेलन होगा। पीएम मोदी ने इस अवसर को विशेष बनाने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि युवा प्रतिभा को पहचान दें, ज्यादा से ज्यादा लोग मराठी सीखें, इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म, भाषिणी जैसी पहल को बढ़ावा दें।

पुरानी सोच पर थमें नहीं रहना है

कवि केशवसुत का एक पद है- जुनें जाऊं द्या, मरणालागुनि जाळुनि किंवा, पुरुनि टाकासडत न एक्या ठायी ठाका, यानी हम पुरानी सोच पर थमे नहीं रह सकते। पीएम मोदी ने कहा कि मानवीय सभ्यता, विचार और भाषा लगातार विकसित होते रहते हैं। आज भारत दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यताओं में से एक है। क्योंकि, हम लगातार विकसित हुए हैं, नए विचारों को जोड़ा है, नए बदलावों का स्वागत किया है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी भाषाई विविधता इसका प्रमाण है। हमारी ये भाषाई विविधता ही हमारी एकता का सबसे बुनियादी आधार भी है।

योगदान में मराठी भाषा और मराठी साहित्य का बहुत बड़ा योगदान था। लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य भी मराठी में ही लिखी थी। उनकी इस मराठी रचना ने पूरे देश में एक नई ऊर्जा भर दी थी।

मराठी भाषा और मराठी साहित्य समाज के शोषित, वंचित वर्ग के लिए सामाजिक मुक्ति के द्वार खोलने के अद्भुत काम का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले, महर्षि कर्वे, बाबा साहेब अंबेडकर जैसे महान समाज सुधारकों ने मराठी भाषा में नए युग की सोच को सींचने का काम किया था। ■

भारत को लेकर दुनिया की निश्चितता का आधार

भारत का तेज विकास

विकसित भारत 2047 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, सरकार चार प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश, समावेशी विकास, विनिर्माण विस्तार और कानूनों का सरलीकरण शामिल है। ऐसे में भारत की तेज ग्रोथ निश्चित मान रही दुनिया के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए फरवरी में असम ने एडवांटेज असम 2.0 और मध्य प्रदेश ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट किया जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन, जहां मिले करीब 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव...

सरकार ने भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें वस्तु एवं सेवा कर की शुरूआत, कॉर्पोरेट कर में कमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, एफडीआई नीति में सुधार, अनुपालन बोझ में कमी के उपाय, सार्वजनिक खरीद आदेशों के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उपाय सहित कई अन्य पहल शामिल हैं। इसके अलावा, भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और निर्यात को बढ़ाने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों की 1.97 लाख करोड़ रुपये खर्च वाली पीएलआई योजनाओं की घोषणा की है जिसमें तेजी से निवेश बढ़ रहा है। इतना ही नहीं सरकार ने भारत 2047 के रोडमैप के हिस्से के रूप में, भारतीय उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ अधिक एकीकरण की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं।

पूर्वोत्तर पर सरकार का फोकस, सेमीकंडक्टर-स्टार्टअप में असम आगे

- पूर्वोत्तर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में है। यही वजह है कि यहां के लिए कई बड़ी विशेष योजनाएं बीते एक दशक में शुरू की गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पीएम-डिवाइन, नार्थ ईस्ट वेंचर फंड, इन स्कीम्स से रोजगार के अनेक नए अवसर बने हैं।
- नॉर्थ ईस्ट के इंडस्ट्रियल पोटेंशियल को बढ़ावा देने के लिए उन्नति स्कीम भी शुरु की है। सेमीकंक्टर का सेक्टर भारत के लिए भी नया है जिसे गति देने के लिए भी असम को चुना है।
- नॉर्थ ईस्ट में जब इस प्रकार की नई इंडस्ट्री लगेगी तो देश और दुनिया के निवेशक वहां नई संभावनाएं तलाशेंगे।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत

2054 स्टार्टअप को मान्यता दी गई अष्टलक्ष्मी में।

1487 स्टार्टअप हैं जिसमें अकेले असम के।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 54 मंत्रालयों को जिम्मेदारी दी गई है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अपने बजट का 10% हिस्सा खर्च करना है।
- नार्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत 30 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिसमें से 10 पूरे हो चुके हैं।
- बीते एक दशक में नॉर्थ ईस्ट में अनेक शांति समझौते हुए हैं, सीमा विवाद में सौहार्दपूर्ण ढंग से प्रगति हुई है जिसे इससे नॉर्थ ईस्ट में हिंसा के मामलों में बहुत कमी आई है। देश को अष्टलक्ष्मी का नया भविष्य लिखना है और इसके लिए सरकार हर कदम उठा रही है।

> 21वीं सदी में दुनिया की प्रोग्रेस, डिजिटल रिवॉल्यूशन, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पर निर्भर है। इसके लिए हमारी तैयारी जितनी बेहतर होगी, दुनिया में हमारी ताकत भी उतनी ज्यादा होने वाली है।
>
> - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

सरकार की नीति और निवेश का ही नतीजा है कि 2025 तक पहली 'मेड इन इंडिया' सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन को लेकर भारत आश्वस्त है तो उन्नत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 85 हजार इंजीनियर को प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया। इस बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर के शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर किए जा रहे हैं।

ग्लोबल अनिश्चितता के बीच भी दुनिया के तमाम विशेषज्ञ अगर किसी एक बात को लेकर निश्चिंत हैं तो वह है - भारत की तेज ग्रोथ। भारत पर ग्लोबल ट्रस्ट बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि आज का भारत आने वाले 25 साल और 21वीं शताब्दी के लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखकर जिस तरह से काम कर रहा है, यही भरोसे का बहुत ठोस

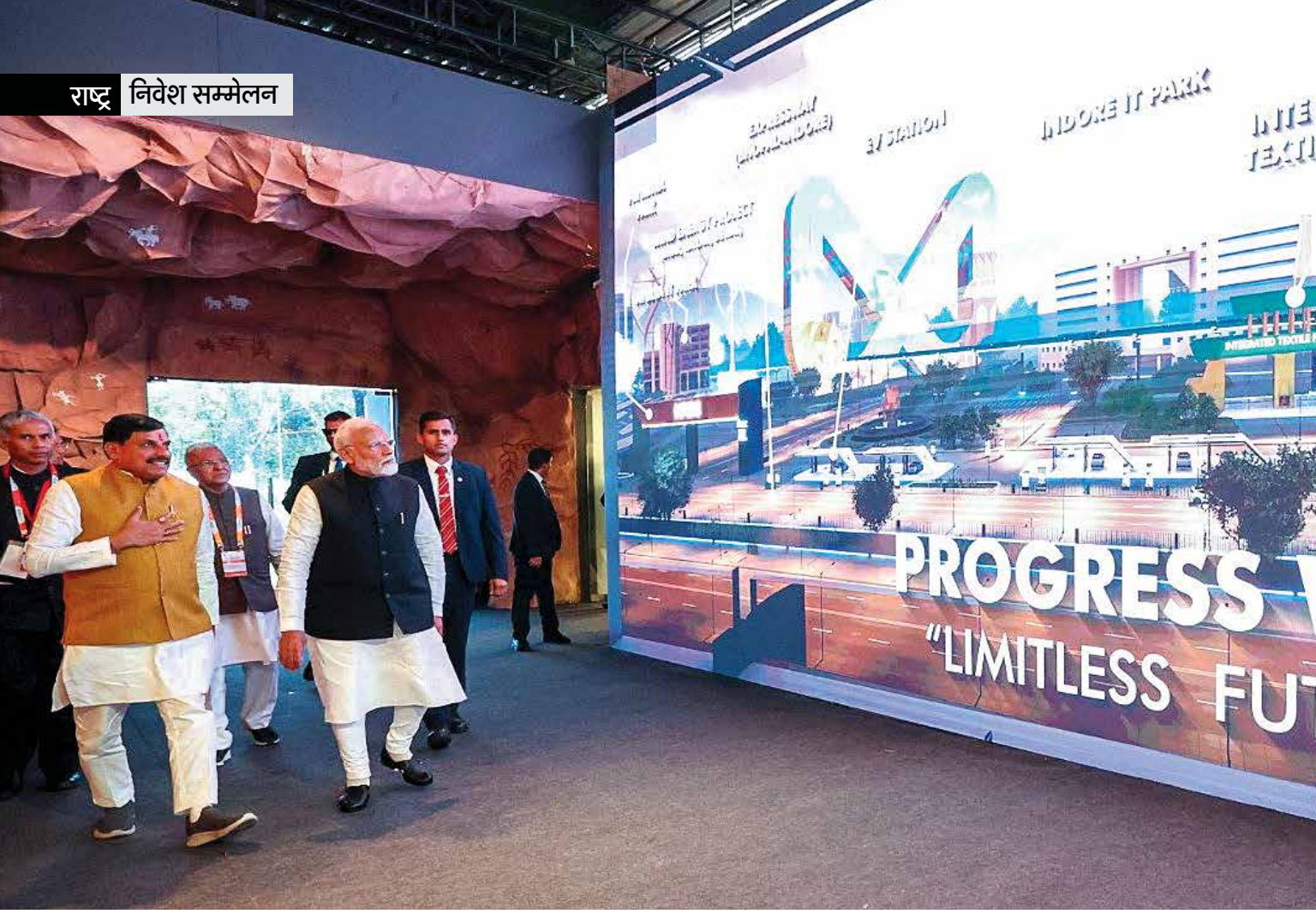

दुनिया का भविष्य भारत के साथ

निवेश यानी भविष्य की मजबूत नींव... जिससे हर सपने को मिलते हैं उड़ने के पंख और उनको आकार देती हैं अनुकूल नीतियां। तेज कनेक्टिविटी, प्रचुर संसाधन और असीमित संभावनाओं के साथ देश का दिल माने जाने वाले मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का जब प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया तो उन्होंने भी इसी बात पर जोर दिया और कहा कि दुनिया का भविष्य भारत में है...

भारत के इतिहास में ऐसा मौका पहली बार आया है जब पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी ऑप्टिमिस्टिक है। पूरी दुनिया में... चाहे सामान्य जन हों, नीति के एक्सपर्ट् हों, विभिन्न देश हों या फिर इंस्टीट्यूशनंस हों... सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं। पिछले कुछ हफ्तों में भारत के बारे में जो टिप्पणियां मिली हैं, उनसे निवेशकों का उत्साहवर्धन होगा। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में दिए गए उस बयान को याद करते हुए कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा, प्रधानमंत्री मोदी ने इस कारण है। दुनिया का भरोसा बहुत तेजी से स्किल्ड होती भारत की युवा आबादी, गरीबी से बाहर निकली नियो मिडिल क्लास और राजनीतिक स्थिरता एवं नीति निरंतरता को सपोर्ट करने वाली 140 करोड़ की आबादी पर है। भारत लगातार सुधार कर रहा है, सप्लाई चेन मजबूत कर रहा है, दुनिया के अलग-अलग क्षेत्र के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है तो नया इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी अनेक नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। आर्थिक क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई शुरू की गई। इंस्टिट्यूशनल रिफॉर्म, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन का यही कॉम्बिनेशन भारत की प्रगति का आधार है।

सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर

क्या है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) 2025

भोपाल में दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) 2025, मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसमें विभागीय शिखर सम्मेलन; फार्मा और चिकित्सा उपकरण, परिवहन और रसद, उद्योग, कौशल विकास, पर्यटन और एमएसएमई आदि पर विशेष सत्र शामिल हैं। इसमें वैश्विक दक्षिण देशों के सम्मेलन, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन सत्र और प्रमुख भागीदार देशों के लिए विशेष सत्र जैसे अंतरराष्ट्रीय सत्र भी शामिल हैं। 50 से अधिक देशों के 100 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि शामिल हुए। जिनमें राजदूत, उच्चायुक्त और महावाणिज्यदूत भी शामिल थे। प्रमुख निवेश क्षेत्रों पर फोकस किए गए, जिनमें कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र एवं परिधान, खनन, आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी विकास और पर्यटन शामिल है।

ऊर्जा के क्षेत्र अग्रणी

समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र में मध्य प्रदेश द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पिछले दशक में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

70 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया गया है पिछले 10 वर्षों में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में

- इस निवेश से पिछले साल अकेले स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र ने 10 लाख से अधिक रोजगार का सृजन किया है। ऊर्जा क्षेत्र में इस उछाल से मध्य प्रदेश को बहुत लाभ हुआ है।
- आज मध्य प्रदेश लगभग 31,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता के साथ बिजली की मांग से अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, जिसमें से 30 प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा है।

बोर्ड परीक्षाओं के चलते खुद देर से पहुंचे पीएम...

मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के चलते भोपाल के छात्रों को सेंटर तक पहुंचने में देरी न हो, इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी निर्धारित समय की बजाय खुद देर से पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचते अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी।

बात पर प्रकाश डाला कि ओईसीडी के एक प्रतिनिधि ने टिप्पणी में कहा कि दुनिया का भविष्य भारत में है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से दिए गए अपने वक्तव्य को दोहराते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश और बढ़-चढ़कर निवेश करने का यह सही समय है।

पीएम मोदी ने गिनाईं खूबियां

मध्य प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से भारत का पांचवां सबसे बड़ा राज्य है, कृषि और खनिज के मामले में भारत के शीर्ष राज्यों में से एक है। मध्य प्रदेश को जीवनदायिनी नर्मदा नदी का आशीर्वाद प्राप्त है। जीडीपी के हिसाब से भारत के शीर्ष पांच राज्यों में से एक बनने की क्षमता है। पिछले दो दशकों में मध्य प्रदेश की परिवर्तनकारी यात्रा की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब राज्य को बिजली और पानी की बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और कानून-व्यवस्था की स्थिति और भी खराब थी। इन परिस्थितियों ने औद्योगिक विकास को मुश्किल बना दिया था। दो दशक पहले लोग मध्य प्रदेश में निवेश करने से हिचकिचाते थे लेकिन आज राज्य निवेश के लिए देश के शीर्ष राज्यों में से एक बन गया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से बढ़ी कनेक्टिविट

पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से बहुत लाभ हुआ है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, जो मुंबई के बंदरगाहों और उत्तर भारत के बाजारों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यहां अब पांच लाख किलोमीटर से ज्यादा का सड़क नेटवर्क है प्रदेश के औद्योगिक गलियारे आधुनिक एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए हैं, जिससे लॉजिस्टिक क्षेत्र में तेजी से विकास सुनिश्चित हो रहा है।

भारत भविष्य की एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं। एडवांटेज असम, असम की अविश्वसनीय क्षमता और प्रगति को दुनिया के साथ जोड़ने की एक बड़ी पहल है। उम्मीद है कि जब देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है तो इस दिशा में पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर अपनी वास्तविक क्षमता प्रदर्शित करेंगे। भारत की ग्रोथ में, असम का कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। 2018 में एडवांटेज असम समिट का पहला एडिशन हुआ था, तब राज्य की इकोनॉमी पौने तीन लाख करोड़ रुपये की थी। अब असम करीब 6 लाख करोड़ रुपये की इकोनॉमी वाला राज्य बन गया है। असम में खूब सारे निवेश ने इसे अनगिनत संभावना वाला राज्य बना दिया है। असम की ग्लोबल ट्रेड में हमेशा से एक हिस्सेदारी रही है।

ऊर्जा, उत्साह और उमंग से भरा 'मेगा झुमोर'

असम की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए 25 फरवरी को गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में 'झुमोर बिनंदिनी' कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में असम की चाय जनजाति और असम के आदिवासी समुदाय के झुमोर नृत्य को एक साथ करीब 8 हजार कलाकारों ने पेश किया जो एक रिकॉर्ड है। समावेशिता, एकता और सांस्कृतिक गौरव की भावना के साथ ही असम के समन्वित सांस्कृतिक मेलजोल का प्रतीक है। यह कार्यक्रम चाय उद्योग के 200 वर्षों और असम में औद्योगीकरण के 200 वर्षों का प्रतीक है।

कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस तरह के भव्य आयोजनों से असम का गौरव तो जुड़ा ही है, इसमें भारत की महान विविधता भी दिखाई देती है।

60 से भी ज्यादा देश के राजदूत भी असम को अनुभव करने के लिए यहां मौजूद रहे।

एक समय था, जब देश में असम और पूर्वोत्तर के विकास की भी उपेक्षा हुई और यहां की संस्कृति को भी नजरअंदाज किया गया लेकिन अब पूर्वोत्तर की संस्कृति का ब्रांड एंबेसडर खुद मोदी ही बन चुका है। असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत झुमोर तक सीमित नहीं है। जहां 2023 में 11 हजार से अधिक कलाकारों ने बिहू का प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था तो भविष्य में बोडो समुदाय के पारंपरिक बागुरुम्बा नृत्य के प्रदर्शन की योजना भी बनाई जा रही है।

वंचित कैंसर रोगियों को मुफ्त उपचार देगा बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी। संस्थान का निर्माण सभी वर्ग के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।

200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले इस कैंसर अस्पताल में वंचित कैंसर रोगियों को मुफ्त उपचार की सुविधा दी जाएगी।

10 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा

पहले चरण में 100 बिस्तरों की सुविधा तैयार होगी। यह अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित होगा तथा इसमें विशेषज्ञ डॉक्टर भी होंगे।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मंदिर, मठ, धाम ये एक ओर पूजन और साधना के केंद्र रहे हैं तो दूसरी ओर विज्ञान और सामाजिक चेतना के भी केंद्र रहे हैं। ऋषियों ने ही हमें आयुर्वेद का विज्ञान दिया, ऋषियों ने ही हमें योग का वो विज्ञान दिया, जिसका परचम आज पूरी दुनिया में लहरा रहा है। जब देश ने मुझे सेवा का अवसर दिया, तो मैंने 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को सरकार का संकल्प बनाया। 'सबका साथ, सबका विकास' के इस संकल्प का भी एक बड़ा आधार- सबका इलाज, सबको आरोग्य है।

पीएम-किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी

बिहार की धरती से अन्नदाता को सम्मान

भारत के भूभाग में 2.9% और आबादी में तीसरे नंबर का राज्य बिहार न सिर्फ पूर्वोदय से भारत उदय के मंत्र की अहम कड़ी है, बल्कि कृषि प्रधान देश के रूप में भारत की भूमिका का अहम हिस्सा भी है। देश के कुल कृषि भूभाग में 5 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी बिहार की है तो कुल अनाज उत्पादन में भी करीब 7 फीसदी की भागीदारी है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अन्नदाताओं को पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त बिहार की धरती से जारी की...

भारत की विकास यात्रा के चार मजबूत स्तंभों में से एक देश के अन्नदाता के उत्थान की दिशा अपनी प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के कार्यक्रम और उपलब्धियों का जिक्र किया तो साथ ही, भागलपुर से बिहार की पावन धरा को भी प्रणाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंद्रांचल की इस धरती पर आना अपने आप में बड़ा सौभाग्य है। इस धरती में आस्था भी है, विरासत भी है और विकसित भारत का सामर्थ्य भी है। यह शहीद तिलका मांझी की धरती है, यह सिल्क सिटी भी है। पूर्वोदय से भारत उदय के अपने मंत्र को दोहराते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार इसका सबसे अहम स्तंभ है। अब विकसित भारत में बिहार का वही स्थान होगा जो प्राचीन समृद्ध भारत में पाटलिपुत्र का था।

किसान हित में उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय था जब किसान संकट से घिरा रहता था,

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6 साल

अब तक किसानों को मिली लगभग **3.7** लाख करोड़ रुपये की सम्मान राशि।

- पीएम किसान की 19वीं किस्त के तहत देश के 9.8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 22 हजार करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर। इसमें बिहार के 75 लाख किसानों के खातों में भेजे गए करीब 1,600 करोड़ रुपये शामिल।
- विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजनाओं में से एक।
- किसानों को 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता।
- पीएम किसान के 85% से अधिक लाभार्थी छोटे-सीमांत किसान।
- पीएम किसान योजना में करीब 25% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं।

पीएम मोदी ने बिहार और राष्ट्र को दी विकास की कई सौगातें

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत **₹33.80** करोड़

के निवेश से मोतिहारी में स्वदेशी नस्लों के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) का उद्घाटन।

- 113.27 करोड़ रुपये के निवेश से बरौनी में दुग्ध उत्पाद संयंत्र का उद्घाटन।
- 526 करोड़ रुपये के निवेश से वारसलीगंज-नवादा-तिलैया रेल खंड (36.45 किमी) के दोहरीकरण का उद्घाटन।
- 47 करोड़ रुपये के निवेश से इस्माइलपुर-रफीगंज सड़क ऊपरी पुल का उद्घाटन।
- 10,000 किसान उत्पादक संगठन राष्ट्र को समर्पित।

बीज से बाजार तक किसानों को मिल रहा केंद्र सरकार का साथ

देश भर में करीब **25** करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए गए।

- बीते 10 सालों में 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि से एमएसपी पर गेहूं, धान, कपास, दलहन और तिलहन फसलों की खरीद की गई।
- 2016 से 2023 तक किसानों को फसल बीमा के 1.72 लाख करोड़ दिए।
- अधिक पैदावार वाले बीज की किस्में 1,390 से बढ़कर 2,900 हुईं।
- वैश्विक दूध उत्पादन में करीब 25% योगदान के साथ भारत पहले स्थान पर।
- 12 लाख करोड़ की उर्वरक सब्सिडी से किसानों को सही समय और किफायती दामों पर खाद मिला।
- परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 15 लाख हेक्टेयर में आर्गेनिक और नेचुरल फॉर्मिंग से 25 लाख से अधिक किसानों को लाभ।
- मुंहपका और खुरपका रोग (एफएमडी) के खिलाफ 100 करोड़ से अधिक टीकाकरण से पशुधन हुआ सुरक्षित।
- कृषि बजट में रिकॉर्ड वृद्धि - 2014 के 22 हजार करोड़ से लगभग 5 गुना बढ़कर इस साल 1.27 लाख करोड़ रु. हुआ।
- ई-नाम प्लेटफॉर्म से 1,400 से अधिक कृषि मंडियां जुड़ी, 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के सुविधाजनक लेनदेन हुए।
- पर ड्रॉप मोर क्रॉप- माइक्रो इरिगेशन कवरेज 42 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 100 लाख हेक्टेयर हुआ।
- 2.25 लाख प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) से आधुनिक कृषि को बढ़ावा।

लेकिन बीते एक दशक में केंद्र सरकार ने उनकी हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। आज किसानों को बीज से लेकर बाजार तक, हर कदम पर केंद्र सरकार का साथ मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार किसानों के बारे में सोचती है, उनकी भलाई के लिए काम करती है। इसलिए यूरिया और डीएपी का जो पैसा किसानों को खर्च करना था, वो केंद्र सरकार खुद खर्च कर रही है। बीते 10 साल

समृद्धि के नए पथ पर बिहार

- आज बिहार में सहकारी दूध संघ, प्रतिदिन 30 लाख लीटर दूध खरीदता है। इसके कारण हर साल, तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक बिहार के पशुपालकों के खातों में पहुंच रहे हैं।
- 10 साल पहले बिहार मछली उत्पादन में देश के 10 राज्यों में से एक था। आज बिहार, देश के टॉप-5 बड़े मछली उत्पादक राज्यों में से एक बन चुका है।
- बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नॉलॉजी एंड आंत्रप्रन्योरशिप की स्थापना की जाएगी। यहां बिहार में कृषि के क्षेत्र में तीन नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किए जाएंगे।
- इस वर्ष के बजट में पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम परियोजना के लिए मदद देने की घोषणा की गई है। इस परियोजना से मिथिलांचल क्षेत्र में 50 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचाई के दायरे में आएगी।
- बिहार सरकार भागलपुर में बड़ा बिजली कारखाना लगा रही है, उसको कोयले की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने कोल लिंकेज को स्वीकृति दे दी है।
- नालंदा विश्वविद्यालय के बाद अब विक्रमशिला में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। जल्द ही केंद्र सरकार इस पर काम शुरु करने वाली है।

8 महीने में 4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा

केंद्र सरकार के लिए बिहार में विकास के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि पीएम मोदी पिछले 8 महीने में 4 बार राज्य के दौरे पर गए और दी विकास की कई सौगातें

- 19 जुलाई 2024 : बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन। विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है।
- 13 नवंबर 2024 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 12,100 करोड़ रुपये लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास कर उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया।
- 15 नवंबर 2024 : 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए पीएम मोदी बिहार के जमुई पहुंचे। वहां उन्होंने 6,640 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
- 24 फरवरी 2025 : पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी। बिहार के भागलपुर से राज्य के लिए कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ।

> “मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन मखाना जरूर खाता हूं। ये एक सुपरफूड है, जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। इसलिए, इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है। यह बिहार के मेरे किसानों की मदद करेगा।
>
> - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

में करीब 12 लाख करोड़ रुपये जो खाद खरीदने के लिए आपकी जेब से जाने थे, वो बच गए। वो केंद्र सरकार ने बजट में से दिए हैं।

10 हजारवां एफपीओ बिहार की धरती पर

किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में किसान उत्पादक संघ (एफपीओ) की भूमिका बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने देश में 10 हजार एफपीओ बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा था। देश ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। बिहार की भूमि 10 हजारवें एफपीओ के निर्माण की साक्षी बन रही है। मक्का, केला और धान पर काम करने वाला यह एफपीओ खगड़िया जिले में रजिस्टर हुआ है। आज देश के करीब 30 लाख किसान इन एफपीओ से जुड़े हैं। इसमें करीब 40 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। ■

विकसित भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण कदम

स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप (SOUL)

भारत जिस विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके लिए जरूरी है कि देश हर क्षेत्र में लीडर्स तैयार करे। यही समय की मांग है। देश को ऐसे लीडर्स तैयार करने होंगे जो ट्रेंड बनाने के लिए नहीं, बल्कि ट्रेंड सेट करने के लिए काम करें। इसमें स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप (SOUL/सोल) बेहद उपयोगी होगा। हर सेक्टर में नए आइडिया और क्रिएटिविटी से नई ऊर्जा पैदा करनी होगी तभी न सिर्फ देश बल्कि वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता रख पाएंगे। इसी दिशा में सोल की स्थापना की जा रही है जो बड़े स्तर पर देश-दुनिया की जरूरतों के हिसाब से तैयार करेंगे अलग-अलग क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता...

दिल्ली के भारत मंडपम में 21 से 22 फरवरी तक सोल लीडरशिप सम्मेलन के पहले संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। दो दिनों तक चले इस सम्मेलन में राजनीति, खेल, कला, मीडिया, आध्यात्मिक दुनिया, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र के नेताओं के जीवन की प्रेरक कहानियों को साझा किया गया। देश का शीर्ष नेतृत्व भी चाहता है कि देश के युवा नए सुझावों के साथ राजनीति के क्षेत्र में आएं। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था कि एक लाख युवाओं को राजनीति में आना चाहिए।

भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। लिहाजा सभी क्षेत्र में गति को बढ़ाने के लिए विश्व स्तरीय नेताओं और अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व की आवश्यकता है। हर क्षेत्र में ऊर्जावान नेताओं की आवश्यकता है जो वैश्विक जटिलताओं का समाधान ढूंढ सके। भविष्य का नेतृत्व केवल सत्ता तक सीमित नहीं होगा, बल्कि नेतृत्व के लिए नवाचार और प्रभावशाली क्षमता भी आवश्यक है। समस्या का समाधान करते समय वैश्विक प्लेटफॉर्म पर भी देश के हित को सर्वोपरि रखे। पीएम मोदी ने कहा कि देश को ऐसे लीडर्स तैयार करने होंगे जो भारतीय मानसिकता के साथ अंतरराष्ट्रीय मानसिकता को भी समझ सके। रणनीतिक फैसले, संकट प्रबंधन और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से अपने को हर पल तैयार रखें। आने वाले समय में डीप-टेक, अंतरिक्ष, बायोटेक और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिए नेतृत्वकर्ता की जरूरत होगी, लिहाजा सोल को इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा। भारत को ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो वैश्विक उत्कृष्टता के नए संस्थान विकसित कर सकें। आज जो नींव रखी जा रही है वह आने वाली पीढ़ियों के लिए गर्व का स्रोत होगी।

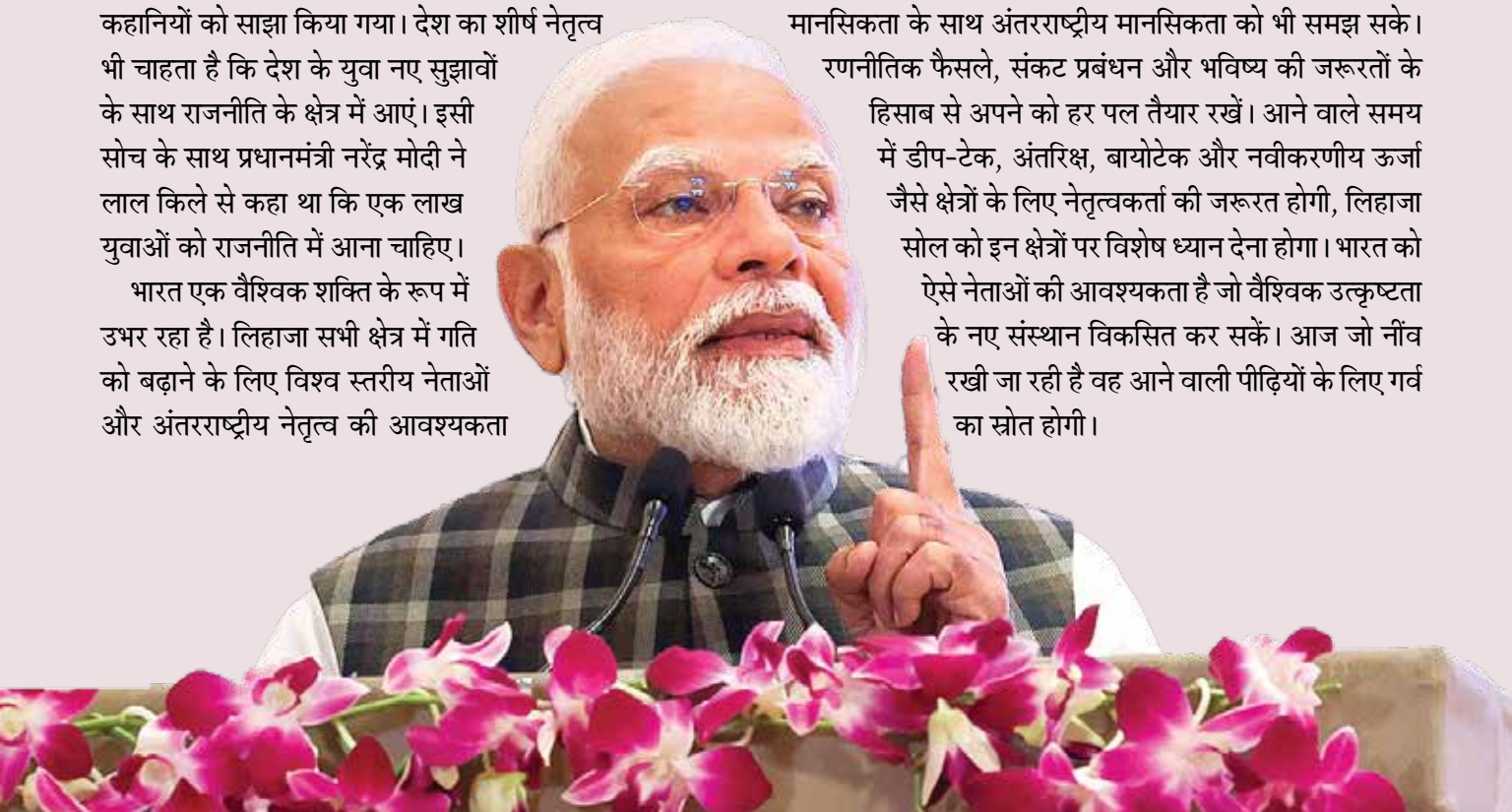

ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसे मंत्र न बनाया जा सके, ऐसी कोई जड़ी-बूटी नहीं है जो औषधि न बन सके और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अक्षम हो।

साझा लक्ष्यों पर पीएम मोदी

- साझा उद्देश्य से बना बंधन खून के रिश्तों से भी होता है मजबूत।
- साझा लक्ष्य और सामूहिक प्रयास से आगे बढ़ने से परिणाम होते हैं सर्वश्रेष्ठ।
- व्यक्ति अपने लक्ष्यों के लिए स्वयं को समर्पित करे तो सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं से करता है काम।
- साझा उद्देश्य टीम भावना की अभूतपूर्व भावना बढ़ाता है।

स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप से ऐसे लीडर निकलेंगे, जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया की संस्थाओं में हर क्षेत्र में अपना परचम लहराएंगें।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

सोल का उद्देश्य

स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप गुजरात में एक नेतृत्व संस्थान है जो जनता के सेवकों को जनहित में आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण के माध्यम से भारत में राजनीतिक नेतृत्व के परिदृश्य को व्यापक बनाना है। इसमें उन लोगों को शामिल करना है जो वंशानुगत राजनीति से नहीं बल्कि सार्वजनिक सेवा के लिए योग्यता, प्रतिबद्धता और जुनून के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। सोल नेतृत्व की जटिल चुनौतियों से निपटने का मार्ग दिखाने के लिए आवश्यक जानकारी, कौशल और विशेषज्ञता लाता है।

प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे नेताओं को तैयार करना आवश्यक है और यह समय की मांग है। पीएम मोदी का मानना है कि सोल सिर्फ संगठन का नाम नहीं है, बल्कि यह भारत के सामाजिक जीवन की आत्मा होगी। भविष्य में गुजरात की गिफ्ट सिटी के निकट सोल का नया और विशाल परिसर बनकर तैयार हो जाएगा। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप ऐसे नेताओं को तैयार करेगा जो राजनीति सहित पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ सकें। सोल आलोचनात्मक सोच, जोखिम लेने और समाधान निकालने की मानसिकता विकसित करेगा। ■

भारत और कतर

एक मजबूत साझेदारी की ओर बढ़ते कदम

दोस्ती, विश्वास और पारस्परिक सहयोग के ऐतिहासिक संबंधों के साथ कतर मध्य पूर्व में भारत का अनन्य सहयोगी रहा है। बीते दशक में दोनों के बीच बढ़ी प्रगाढ़ता की झलक कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी के दो दिवसीय भारत दौरे में भी दिखाई दी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल को तोड़कर एयरपोर्ट पर स्वयं उनकी आगवानी की। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी औपचारिक भोज में उनका स्वागत कर कहा कि हमारे सदियों पुराने संबंधों की झलक हमारे लोगों की पसंदीदा कला, संगीत और भोजन में देखी जा सकती है, वाहे वह बिरयानी हो या कड़क चाय...

कतर की कुल आबादी में करीब 25 फीसदी भारतीय प्रवासी तो भारत के गैस आयात में कतर की 70 फीसदी की हिस्सेदारी दोनों देशों के संबंधों की मजबूत को दर्शाते हैं। यही नहीं, दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की ओर विकसित एवं विकासशील राष्ट्र आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं तो कतर भी इसमें अपना योगदान बढ़ाना चाहता है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी ने 17-18 फरवरी को अपने भारत दौरे पर दोनों देशों के बीच और मजबूत भविष्य की नींव रखी।

भारत-कतर ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए कतर ने भारत में कतर निवेश प्राधिकरण (क्यूआईए)

भारत-कतर के बीच इन निर्णयों से खुलेंगे नए अवसर...

- द्विपक्षीय रणनीतिक भागीदारी की स्थापना।
- आय पर टैक्स और उसके प्रोटोकॉल के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए संशोधित समझौता।
- वित्तीय और आर्थिक सहयोग पर भारत के वित्त मंत्रालय और कतर के वित्त मंत्रालय के बीच समझौता।
- युवा मामले और खेल के क्षेत्र में सहयोग।
- दस्तावेजों और अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग।
- इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट कतर के बीच समझौता।
- भारतीय उद्योग परिसंघ और कतर व्यवसायी संघ के बीच समझौता।

इन पर बनी सहमति...

- सीमा सहित आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा। ऐसे खतरे से निपटने के लिए आपसी सहयोग पर सहमति।
- सूचना और खुफिया जानकारी साझा करने, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध और अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति।
- कतर ने भारतीय दवा उत्पादों और चिकित्सा उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा देने की जताई इच्छा।
- प्रवासियों, श्रमिकों की गरिमा, सुरक्षा और आपसी हित के मामलों का समाधान करने के लिए श्रम और रोजगार पर संयुक्त कार्य समूह की नियमित बैठक होगी।
- दोनों पक्ष ने सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं में सुधार को जरूरी बताया। संयुक्त राष्ट्र में एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ सहयोग और समर्थन करने पर सहमति जताई, जिसमें बहुपक्षीय मंचों पर एक-दूसरे की उम्मीदवारी का समर्थन करना भी शामिल है।
- ई-शासन को आगे बढ़ाने और डिजिटल क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर सहमति।

कार्यालय खोलने का निर्णय लिया। इसका भारत सरकार ने स्वागत किया। कतर ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने में भारत द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। कतर ने इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रौद्योगिकी, निर्माण, खाद्य सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स, आतिथ्य और आपसी हित के अन्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने में रुचि व्यक्त की है। भारत में बढ़ते व्यापारिक माहौल को देखते हुए कतर ने भारत में 10 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है।

भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग का एक मजबूत स्तंभ रहा है, जिसे आगे बढ़ाते हुए दोनों देश अब नए-नए क्षेत्र में साथ मिलकर काम करेंगे ताकि संबंधों को और मजबूती मिल सके। नव स्थापित रणनीतिक साझेदारी को देखते हुए दोनों पक्ष ने राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संस्कृति, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्थायित्व और लोगों के आपसी संबंधों के साथ संरचना आधारित सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ने का निर्णय लिया है।

आर्थिक विकास को गति देने में व्यवसायों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वाणिज्यिक साझेदारी को बढ़ावा देने, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने, विविधता लाने और निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापार प्रदर्शनियों के महत्व पर जोर दिया। कतर में क्यूएनबी बिक्री केंद्रों में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के संचालन का भारत ने स्वागत किया और उम्मीद जताई है कि जल्द ही कतर में यूपीआई की राष्ट्रव्यापी शुरुआत होगी। दोनों देश अपनी-अपनी मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार के निपटान की संभावना तलाशने पर सहमत हुए। ■

मिथिला पेंटिंग से रचा इतिहास, मिला पद्म श्री सम्मान

बिहार की दुलारी देवी को न पढ़ना आता है और न लिखना। वह समाज के सबसे निचले पायदान से आती हैं। गरीबी और मुसीबतों ने इन्हें तोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन हार मानने की बजाय वह दोगुनी ताकत के साथ उठ खड़ी हुईं। उनके हाथों ने जब कूची थामी तो मिथिला पेंटिंग के रूप में उनकी कला दुनिया के सामने रंग बिखेरने लगी। 2021 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उनकी मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पहन कर पेश किया देश का बजट...

यह कहानी है बिहार के दुलारी देवी की, जिनका जन्म ही अभाव और गरीबी के बीच हुआ। बेहद ही गरीब मल्लाह परिवार में जन्मीं दुलारी देवी की कम उम्र में ही शादी हो गई और बच्चे हो गए लेकिन मसीबतों ने पीछा नहीं छोड़ा। गरीबी और मुसीबतों से घिरी दुलारी देवी दूसरों के घरों में झाड़ू-पोंछा लगाने लगीं लेकिन नसीब को कुछ और ही मंजूर था। हाथ में पोंछे की जगह कूची ने ले ली। इसके बाद मिथिला पेंटिंग बनाने का जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया वो आज तक नहीं रुका। आज उनकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, मिथिला पेंटिंग जिसने देश-विदेश में उन्हें पहचान दिलाई।

जब पद्म श्री देने की घोषणा की गई थी तब उनका दर्द इन शब्दों में छलक पड़ा था, "बहुत कष्ट से गुजरी हूं। बहुत संघर्ष में रह कर मिथिला पेंटिंग सीखी। मुझे बहुत खुशी है।" राष्ट्रपति भवन में पद्म सम्मान लेने के बाद उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को एक पेंटिंग भी उपहार में दी थी। इस उपहार के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने कहा था, "दुलारी देवी जी उन लोगों में से हैं जिन्हें पीपुल्स पद्म से सम्मानित किया गया है। वह एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं जो बिहार के मधुबनी की रहने वाली हैं। समारोह के बाद पुरस्कार विजेताओं के साथ अनौपचारिक बातचीत के समय उन्होंने मुझे अपनी कलाकृति भेंट की। उनका अभिनंदन और आभार।"

इतना ही नहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब अपना 8वां बजट पेश किया तो उनसे बिहार को काफी उम्मीदें थी जिसे उन्होंने पूरा भी किया। साथ ही, उनकी साड़ी भी काफी सुर्खियों में रही जिसका बिहार कनेक्शन था। दरअसल उन्होंने जो साड़ी पहनी थी वह मिथिला पेंटिंग से सजी थी जिसे दुलारी देवी ने बनाया था। दुलारी देवी ने निर्मला सीतारमण को यह साड़ी उस समय विदाई में दी थी जब वह मधुबनी के मिथिला चित्रकला संस्थान आई थीं। साथ ही बजट के दिन उनसे यह साड़ी पहनने का अनुरोध भी किया था। बैंगलोरी सिल्क वाली यह साड़ी तैयार करने में दुलारी देवी को एक महीने का समय लगा था। इस साड़ी में जुड़वा मछली और कमल के फूल की पेंटिंग की गई थी। मिथिला में मछली, मखाना और पान बहुत प्रसिद्ध है।

मिथिला पेंटिंग पूरी तरह हाथों से बनाई जाती है जिसमें देवी-देवताओं, प्रकृति, पौराणिक कथा और विवाह से जुड़ी चित्रकथाएं होती हैं। इसे खासतौर पर प्राकृतिक रंगों से तैयार किया जाता है जिससे यह साड़ी पर्यावरण के अनुकूल होती है। मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी की यह खासियत ही इसे आम साड़ी से सबसे अलग और खास बनाती है। यह सिर्फ एक परिधान नहीं बल्कि बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी माना जाता है।

Narendra Modi
@narendramodi

बीते 10 वर्षों में हमारे प्रयासों से देश में कृषि क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है। हमारे लाखों छोटे किसानों को मिल रही आर्थिक मदद से बाजार तक उनकी पहुंच बढ़ी है। इसके साथ ही कृषि की लागत कम हुई है और उनकी आय में भी वृद्धि हुई है।

#PMKisan

रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India
@DefenceMinIndia

Indian Coast Guard की स्थापना से लेकर अब तक, हम इसकी यात्रा पर नज़र डालें, तो हम देखते हैं, कि एक छोटी शुरुआत से बढ़ते हुए, यह force, आज एक Formidable force के रूप में विकसित हुआ है। आज, हमारी coast guard, दुनिया की सबसे Perfect and efficient, Marine forces में से एक है। हमारे Coast guard को, न केवल हमारे देश के भीतर, बल्कि Global community के बीच भी trustworthy force के रूप में देखा जाता है। यह Indian Coast Guard की, निश्चित ही एक बड़ी उपलब्धि है: रक्षा मंत्री श्री @rajnathsingh

Amit Shah
@AmitShah

भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) पारंपरिक बीजों के संरक्षण-संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है।

आज नई दिल्ली में BBSSL के मीठे बीजों से संबंधित बैठक की अध्यक्षता कर फलों, सब्ज़ियों और खाद्यान्न के मीठे बीजों के डेटाबेस के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। साथ ही, BBSSL विभिन्न क्षेत्रों के चुनिंदा पारंपरिक बीजों के जैविक उत्पादन तथा बाजार में उनकी व्यापक उपलब्धता भी सुनिश्चित करे।

Nitin Gadkari
@nitin_gadkari

स्पेस सेक्टर हो, या फिर AI, हमारे युवाओं की बढ़ती भागीदारी एक नई क्रांति को जन्म दे रही है। नई तकनीक को अपनाने और आजमाने में भारत के लोग किसी से पीछे नहीं हैं। - प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी

#MannKiBaat

Piyush Goyal
@PiyushGoyal

#PMKisan के 6 वर्ष, किसानों का उत्कर्ष!

DBT के माध्यम से सीधे बैंक में आर्थिक सहायता, MSP पर ऐतिहासिक खरीद, बेहतर बाजार तक पहुंच, कृषि बजट में बढ़ोतरी और ऐसे कई आधुनिक सुधारों के साथ मोदी सरकार लगातार किसानों को सशक्त बना रही है।

हमारे अन्नदाताओं के सम्मान, समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री @NarendraModi जी का आभार।

Kiren Rijiju
@KirenRijiju

बीता दशक भारत के लिए एनर्जी सेक्टर की अभूतपूर्व ग्रोथ का रहा है।

खासतौर पर ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत ने वो कर दिखाया है, जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी: माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी

#GlobalInvestorsSummit

45 दिन

महाकुंभ में संगम तट पर सिमटी दुनिया, देखा सनातन का वैभव

पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई पुण्य की डुबकी

एडवांटेज असम 2.0 निवेश एवं अवसंरचना शिखर सम्मेलन के उद्घाटन किया

देश की आर्थिक वृद्धि निश्चित:मोदी

भरोसा

सेमीकंडक्टर चिप्स से तैयार भेंट की पूरी भेंट की

रिलायंस 50 हजार करोड़ का निवेश करेगी : अंबानी

विश्व का भविष्य भारत में, निवेश का यही सही समय : पीएम मोदी

भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का किया उद्घाटन

विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेने रूस जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी

पुतिन के निमंत्रण पर इस साल में तीसरा दौरा, अमेरिकी यात्रा के बाद माना जा रहा बेहद अहम

इसलिए अहम है यात्रा

राज्य के वैश्विक निवेश सम्मेलन इंवेस्ट मध्यप्रदेश का पीएम ने किया उद्घाटन

अदाणी, एनटीपीसी, रिलायंस समेत कई कंपनियां चार लाख करोड़ निवेश करेगी मप्र में

होली से पहले पीएम ने बिहार से अन्नदाताओं को दिया बड़ा तोहफा

22 हजार करोड़ की किस्त जारी की

वीरों को नमन

शहीदी दिवस – 23 मार्च

1919 का साल था। अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया था। नरसंहार के बाद 12 साल का एक बच्चा घटना स्थल पर गया। उस बालक ने वहां जो देखा वह उसकी सोच से परे था। वह यह सोच कर स्तब्ध था कि कोई इतना भी निर्दयी कैसे हो सकता है। वह मासूम गुस्से की आग में जलने लगा था। वहीं बाग में उसने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने की कसम खाई। वह बालक कोई और नहीं बल्कि भगत सिंह थे। अपने जीवन की चिंता की परवाह किए बगैर भगत सिंह और उनके साथियों ने ऐसे साहसी कार्यों को अंजाम दिया जिसका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे गई। वे जब तक जिए उनका एक ही मिशन था, भारत को अन्याय और अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाना...

“आजादी के क्रांतिदूत अमर शहीद वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीदी दिवस पर शत-शत नमन। मां भारती के इन महान सपूतों का बलिदान देश की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणास्त्रोत बना रहेगा।

जय हिंद!

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

न्यू इंडिया समाचार
पाक्षिक

आर.एन.आई, DELHIN/2020/78812, 16-31 मार्च, 2025

आरएनआई DELHIN/2020/78812, दिल्ली पोस्टल लाइसेंस नंबर- DL (S)-1/3550/2023-25 डब्ल्यूपीपी संख्या- U (S)-98/2023-25, posting at BPC, Market Road, New Delhi - 110001 on 13-17 advance Fortnightly (प्रकाशन तिथि- 3 मार्च 2025, कुल पृष्ठ-56)

प्रधान संपादक:
धीरेन्द्र ओझा, प्रधान महानिदेशक,
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक और मुद्रक:
योगेश कुमार बवेजा,
महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो

कमरा संख्या-278, केंद्रीय संचार ब्यूरो,
सूचना भवन, द्वितीय तल,
नई दिल्ली- 110003 से प्रकाशित

मुद्रण: जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा. लि.,
बी-278, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1,
नई दिल्ली-110020